[Shri A. C. George]

(4) A copy of the Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Cardamom Board, Ernakulam for the year 1969-70 and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 19 of the Cardamom Act, 1965. [*Placed in Library. See.* No. LT-357/71]

(5) A copy of the Annual Report of the Coffee Board for the year 1969-70. [*Placed in Library. See.* No. LT-358/71]

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :—

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 7th June, 1971, agreed without any amendment to the General Insurance (Emergency Provisions) Bill, 1971, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd June, 1971."

12.23 hrs.

GENERAL BUDGET, 1971-72--GENERAL DISCUSSION—Contd.

MR. SPEAKER : The House will now take up general discussion of the general budget. We have still 5 hours and 15 minutes. When would the Minster like to reply ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : I would like to reply some time tomorrow, either 3 O'Clock or 4 O'Clock. 4 O'Clock would suit me very well. I will take 50 minutes to 1 hour.

MR. SPEAKER : Shri Shivpujan Shastri will continue his speech.

श्री शिवपूजन शास्त्री (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का बजट हमें एक नई दिशा की तरफ ले जाता है, इस लिये वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह बजट देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में है। देश की आर्थिक स्थिति तरक्की पर है, खासकर कृषि उत्पादन 5 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन 5 प्रतिशत अधिक बढ़ा है, लेकिन जितना होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। खासकर खाद्यान्न 100 प्रतिशत अधिक हो रहा है। 1950 में 5 करोड़ टन अन्न होता था लेकिन 1971 में 10.5 करोड़ टन हो रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन दिन दिन बढ़ रहा है। अभी मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा कि जिन खेतों में एक फसल होती थी, उन में तीन फसलें निकालने की तैयारी हो रही है। मई और अप्रैल के महीने में जहां पर पहले कुछ नहीं होता था वहां धान बोया जा रहा है। इस मामले में लोग विज्ञान से भी मदद ले रहे हैं और गावों में भी खेती के लिये ट्रैक्टरों का व्यवहार कर रहे हैं। अगर इस तरह से देखा जाय तो देहातों में कृषि उत्पादन काफी तरक्की पर है। कमी सिर्फ इस बात की है कि जो किसान एक बीघा या पांच बीघे तक भूमि में खेती करते हैं वह ट्रैक्टर को व्यवहार में नहीं ला सकते हैं और अच्छी खाद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन के लिये खाद और ट्रैक्टरों का इन्तजाम किया जाना चाहिये।

जहां तक पिछले वर्षों का सवाल है, मंत्री महोदय उन को ध्यान में रखते हुए आगे के लिये विचार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। उत्पादन में जो कमी है उस के लिये मंत्री महोदय जिम्मेदार नहीं हैं। उस के लिये देश में काफी जागरूकता लाने की जरूरत है और

लोगों में उत्पादन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आज कल हम देखते हैं कि देश में उन चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं जिन पर टैक्स नहीं लगाया गया हैं। इस का मतलब यह है लोगों की आदत खराब हो गई है। लोग एक नई आदत सीख चुके हैं और वह यह है कि चीज को चुरा कर, नक्ली कमी कर कर के उस को मंहगा कर देते हैं। इस आदत के खिलाफ देश भर में एक नई जागरूकता लाने के लिये तहरीक चलनी चाहिवे। यह बजट की कमी नहीं है, यह हम माननीय मदस्यों की कमी है कि हम देश में ऐसा वातावरण नहीं तैयार कर रहें हैं जिस में लोग नाजायज तरीके इस्तेमाल न कर सकें।

अब हम कुछ बजट प्रस्तावों को देखें। लेकिन उस के पहले हम बजट के खर्चे पर भी विचार करें। बजट के खर्च को पूरा करने के लिये 177 करोड़ रु. के टैक्स लगाये गये हैं और 220 करोड़ रु० का घाटा छोड़ दिया गया है। लेकिन यह 177 करोड़ रु० बजट में किस काम के लिये रक्खा गया है ? जो भी प्रत्यक्ष कर हैं, हम देखते हैं कि कोई भी आदमी उन का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि यह टैक्स उन लोगों पर लगाये गये हैं जिनसे रुपया लेना चाहिए, जिनके बारे में ऐलान किया है कि हम उन से लेंगे जिन के पास है और उस को हम उन लोगों पर खर्च करेंगे जिन के पास नहीं है। बजट में ठीक वैसा ही किया गया है। जो प्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं उन से प्राप्त होने वाला रुपया उन लोगों के लिये रक्खा गया है जिन को उसकी जरूरत है। मैंदे पर जो टैक्स लगाया गया हैं उस से 7करोड़ रु० वसूल होगा, वह सारा बच्चों के लिये खर्च किया जा रहा है। क्या बच्चों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये मैंदे पर कर लगाना जरूरी नहीं है। इस तरह से देखा जाय तो जितने भी खर्च की मदें है कोई भी नहीं कह सकता है कि उन को काम में नहीं लाया जाना चाहिये। हमारे वित्त मंत्री जी वे जान बूझ कर उन्हीं मदों को रखा है जिन पर खर्च करना बहुत जरूरी है।

जहां तक घाटे के बजट की बात है वह पहले से ही चला आ रहा है, और इस साल घाटे की मद पारसाल से कम है। इस तरह से हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घाटे का बजट न होने पाये, लेकिन वह एक दो साल में नहीं हो सकता, उस के लिये कुछ और वक्त चाहिये।

जहां तक समाजवाद का सवाल है, वह तो एक प्रक्रिया है। एक जीवन की राह है। उस के पीछे सिद्धान्त इतना ही है कि समान अवसर सब को मिलना चाहिये, हर एक व्यक्ति को जीने का अवसर मिलना चाहिये। यह अवसर तभी होगा जब जिन लोगों के पास जीवन के ज्यादा साधन हैं, उन से उन को ले कर ऐसे लोगों को दें जिन के पास वह साधन नहीं हैं। यह बिल्कुल जायज है यह सामाजिक न्याय के अनुकूल है। इस तरह से हम देखते हैं कि बजट के जितने प्रस्ताव हैं वे एक सिद्धान्त के अनुकूल हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके सिद्धान्त कुछ अलग ही प्रकार के होंगे। जो समाजवादी लोग हैं, जो लोग आर्थिक जीवन को पूरे राज्य के हाथ में रखना चाहते हैं उनका राज्य भी एक नई किस्म का होता है, जिस में तानाशाही का मौका होता है। हम उस राज्य कला को, राज्य चलाने के कार्य को पसन्द नहीं करते हैं। हम तो ऐसा राज्य चाहते हैं जिस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से विकसित होने का अधिकार मिले। प्रत्येक व्यक्ति को वह अधिकार तभी मिलेगा जब उसको बराबर के अवसर मिलेंगे। इस बजट में बराबर के अवसर देने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

SHRI S. S. MOHAPATRA (Balasore) : Mr. Speaker, Sir, listening for so many hours to the discussion on the Budget, as a teacher of political economy for many years and also as a student, who has read economics and politics, I can only say in this House that this Budget cannot be called a socialist budget but it is a budget which has processed the fundamentals which will go to shape the socialist economy of our state in future. As the Minister, Shri Ganesh, told us the other day, this only budget cannot initiate the process of socialism ; there will be many more budgets in this country to be propounded and given to the people by this Government, which will make the sum total of our socialist realisation.

I have listened to the arguments of learned Members in the Opposition who have said that this is not a socialist budget. I have my own conviction that it is very difficult to bring a socialist budget in a democratic set-up. Unless we have partial dictatorship, it is very difficult to control the means of distribution and production in this country. I believe, Shrimati Indira Gandhi, who has been given a mandate by the people to bring socialism to this country can also act as a partial dictator *(Shri Piloo Mody* : She is.) with full cooperation of the people of this country to bring economic resurgence in this sub-continent.

We have heard the budget speeches of previous ministers in this independent country. We have heard Shanmugham Chetty ; we have heard Dr. John Mathai ; we have heard Shri Deshmukh ; we have heard Shri Morarji Desai ; but Shri Chavan's budget has evoked full throated hopes in this country and the country expects that in course of time this budget will be the forerunner of further socialist budgets.

I must say that nothing more could be expected in a country which passed through a non-violent revolution. It is possible for Soviet Russia to give socialist budgets in five years' time and it has not been given in Soviet Russia. We have been hearing from the Soviet leaders that free bread will be available to the Soviet people. The Bolshevik Revolution came in 1918 and this is 1971 ; during all these years the Soviet people have not got free bread. So I say, in the present circumstances nothing more could be expected of this Government. Probably for the first time in the economic as well as the political history of India this Government has aroused hopes and we can expect that the future budgets will definitely be according to the liking of the people.

We have heard criticism that additional taxes have been imposed on cigarettes, textiles, petrol, telegrams and telephones and that there has been a ceiling on company remuneration. But I must say that this country has to be roused to a sense of supreme sacrifice, no country can achieve socialism. The people of Russia, China, Hungary, Rumania, Yugoslavia, Czechoslovakia—all the socialist countries, whatever, we may name them—must have made the supreme sacrifice for bringing socialism. But we people in our country do not have that spirit of socialist realisation and of sacrifice.

We know, the ministers are living a life of luxury. We know even a parliamentarian like myself, who has been elected by the downtrodden people, who are unfed and unclad, leads a life which I should not lead. At least 50 per cent of remuneration that I get should go to the people. So I say, unless we are roused to the sense of supreme sacrifice, nobody can achieve socialism in this country ; socialism will be a hyperbolic nonsense and will never be reality.

The rich agriculturists should have been taxed more in this budget. In Russia the rich kulaks were found to be counter-revolutionary and reactionaries. The Bolshevik Government tried to control them there was a revolution against them. The rich landed peasantry in this country has closed the door for an agrarian revolution. There should be distribution of land and of the national wealth. Then only the common people, the peasants and workers, may realise that here is a government which can give us socialism. This government is bound to be a workers' and peasants' government some day. Then only we can have socialism. When we will find that this government has representation of the workers and peasants—that is what Pandit Nehru thought of and what late Gandhiji also aspired to—then only we can

feel that the future budgets will be in the line of popular thinking and popular desire.

Shri Chavan, the Finance Minister, has earmarked Rs. 60 crores for Bangla Desh. Bangla Desh is a great problem not only for us but for the whole world. It is an international responsibility. But people outside in the country, 55 crores of Indians, feel that probably the India Government could have acted more vigorously, does not matter if it would have amounted to a sense of a little aggression across the border. Rs. 60 crores is nothing. Shri Chavan has shown his supreme sense of financial calculation by trying to narrow the balance of payments gap and all that, thereby trying to secure the economic foundation of this country. But Bangla Desh is a foreign relation question which is very much tied up with our foreign policy.

Our foreign policy is a socialist foreign policy. Long back when Sir Girija Shankar Bajpai was controlling our foreign relations, one of our ambassadors met Sir Vincent Aureol and talked to him about Indian foreign relations. Sir Vincent Aureol said, "I can understand very much about the first sex and the second sex, but your foreign policy is the third sex in politics." For many years it was so, but Nehru changed the very courte of Indian foreign policy. Shrimati Gandhi is today following the path which was shown by the late Panditji, of non-alignment. The Bangla Desh question is bound to be a burning question for many years to come and not only Rs. 60 crores but it may so happen the finance Minister has to keep apart Rs. 600 crores for such questions.

Shri Chavan has earmarked Rs. 25 crores for the educated unemployed people. Here I must say that Shri Chavan has not realised the feelings of the vast multitude of unemployed people in this country. I come from a place where probably 90 per cent of the people are in hunger. Rs 25 crores is nothing. We assured the people before the elections that probably from every family one one will get a job somewhere who will get his food. If India has 55 crores of people and there are 4 crores or 5 crores of families, how are we going to employ these 5 crores of unemployed people ?

The unemployed people are becoming Naxalities. The cream of unversities, people who topped in universities in West Bengal are becoming Naxalites, because they are unemployed. They do not get food to eat ; they do not have proper clothing ; they see their fathers dying of hunger and their mothers cannot give a morsel of food to the dying children. What will be their reaction ? These educated unemployed people, who got first division in unversities brilliant technicians and scientists, do not get any employment. What will be their mental reaction ? The reaction will be the that they will/turn into either Naxalites or militant socialists or anything that you may call it. You have to think about these unemployed people and have a crash programme. Now, Rs. 12 lakhs have been given to every district. What will happen ? In a block, one hundred people are to be given employment now I know thousands are there who are not getting food to eat. We are thinking of giving employment to only 100 people in a block. It is nothing, even a collection of pebbles on the seashore. The hon. Finance Minister has to think on this line.

In conclusion, I say, the country has reposed confidence in him, the country has reposed confidence in the Prime Minister and the country thinks, feels and hopes very strongly that socialism is around the corner.

श्री गंगा चरण दीक्षित (खंडवा) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने 1971-72 के लिए जो आय व्ययक प्रस्तुत किया है, मैं उस का समर्थन करता हूं। जब कोई भी विकासशील देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी आर्थिक उन्नति और समृद्धि के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उस को नाना प्रकार के अवरोधों, विरोधों, आलोचनाओं और निन्दाओं का सामना करना पड़ता है। विकासशील देशों में बजट बनाते वक्त आर्थिक उन्नति और वित्तीय स्थिति में संतुलन लाने के लिए

[श्री गंगा चरण दीक्षित]

जनसाधारण पर किसी न किसी प्रकार का बोझ डालना ही पड़ेगा।

यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि सरकारी पूंजी निवेश में बढ़ोतरी किये बिना हम अपने देश की अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते। इस बजट से यह बात स्पष्ट झलकती है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था इतनी जड़ता की दयनीय व्यवस्था में पहुंच गई है कि वित्त मंत्री के लिए सिवाये इधर से कुछ तोड़ने और उधर से कुछ जोड़ने के और कोई चारा नहीं था। लेकिन इस जोड़ने और तोड़ने में भी उन्होंने बड़े कौशल के साथ प्लास्टिक सर्जरी की और इस चातुर्य के साथ बजट को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हमें उस की सराहना ही करनी पड़ती है।

ऐसा मालूम पड़ता है कि वित्त मंत्री गीता के बड़े उपासक हैं और वह गीता के जीवन-दर्शन को हमारे वित्तीय क्षेत्र में उतारना चाहते हैं। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा है, यह बजट त्याग की अपेक्षा करता है। जब तक इस देश में त्याग की भावना नहीं आयेगी, तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार, हमारे देश की प्रगति और हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो सकती। एक बात जरूर है कि यह बजट त्याग की अपेक्षा तो जरुर करता है, लेकिन "तेन त्यक्तेन भुंजीथाः" की शर्त पूरी होना अभी बाकी है। जनसाधारण पर केवल कुछ कर लगाया गया है। यदि हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारा जनसाधरण तनिक भी करभार के भार से न दबे, तो हम ने जो स्वतन्त्रता प्राप्त की है, उसकी किस प्रकार हम रक्षा कर सकेंगे ? स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन प्राप्त की हुई स्वतंत्रता की रक्षा करना उस से भी ज्यादा कठिन है। इस लिए यदि जनसाधारण पर कुछ थोड़ा सा कर भार आ जाता है, तो उस को लेकर शोर मचाना या नकरात्मक नारे लगाना ठीक नहीं है।

जहां तक करों का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने एक से चार तक पावरलूम चलाने वालों को संयुक्त उत्पादन-शुल्क में कुछ छूट दी है। मैं उस की तारीफ करता हूं। लेकिन में उन से यह अपेक्षा करता था कि वह एक से चार पावरलूम चलाने वालों के संयुक्त उत्पादन-शुल्क को पचास रुपये से दस रुपये करने के साथ साथ उन पर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को भी हटा देंगे, ताकि ग़रीब बुनकरों को काफी राहत मिल सके। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो चार इकाई से ऊपर लूम चलाते हैं, उन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम है, बल्कि जो पावर-लूम पर टेरिलीन, नाईलोन और रेशम बनाने वाले है, उन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नही है और उन्हे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ता है। वित्त मंत्री महाराष्ट्र से आते हैं, जहां विद्युत-चालित करघे भारतवर्ष में सब से ज्यादा चलते हैं। अगर वह एक से चार पावरलूम चलाने वालों को संयुक्त उत्पादन-शुल्क में राहत दे सकते हैं, तो मैं उन से यह आशा करता हूं कि वह उन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी माफ कर देंगे।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि सब राज्य सरकारों में समानता रहेगी, असमानता नहीं। यह एक साहसी कदम है। लेकिन मुझे यह देख कर हैरानी होती है कि एक प्रान्त स्टेट बैंक की शाखायें पावरलूम वालों को 2200 रुपये का लोन देती है, जब कि उस के पास के ही दूसरे प्रान्त में उसी स्टेट बैंक की शाखायें 750 रुपये का लोन देती है। मैं इस सम्बन्ध में स्टेट बैंक के मैनेजरों से मिला। मैं ने उन से पूछा कि क्या कारण है कि महाराष्ट्र में एक पावरलूम

को 2200 रुपये लोन मिलता है, जब कि महाराष्ट्र के साथ लगे हुए मध्य प्रदेश में एक पावरलूम को 750 रुपये से ज्यादा लोन नहीं दिया जाता है। उन्होंने केवल यही बताया कि हम स्थानीय परिस्थितियों को देख कर ऋण देते हैं। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें और दो राज्यों के साथ बरते जाने वाली असमानता को दूर करें।

कुछ चीजों को विलासिता की चीजें कह कर यदि हम उन पर टैक्स लगायें, तो वह समझ में आता है। मैं देखता हूं कि वित्त मंत्री ने हरिजन और आदिवासी आदि पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए पब्लिक स्कूलों में पच्चीस प्रतिशत स्थान रिजर्व किये हैं। ताकि वे जा कर समाज के साथ बराबर से एक कन्धा लगा कर काम करें। समझ में नहीं आया कि एक ओर तो हम यह कोशिश करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग हमारे कन्धे से कन्धा लगा कर हमारे समकक्ष और हमारे साथ बैठें, लेकिन जब शिक्षित हो जायं तब अगर वह बिजली का बल्ब लगाने की कोशिश करें या चीनी के बर्त्तन में खाना चाहें या वह साबुन का उपयोग करना चाहें तो उन को ज्यादा खर्च करना पड़े। इन को भी यदि हम विलासिता की चीजें समझें तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत जब यह देखेगा कि भारतवर्ष में साबुन, चीनी के बर्त्तन बिजली का बल्ब यह भी विलासिता के अंदर गिने जाते हैं तो यह जरा शर्मनाक बात भारत के लिए होगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह पहला ही बजट नहीं है जो कि घाटे का बजट है। इस के पहले भी घाटे के बजट आए और उन बजटों को हमने पचाया। इस से पहले जितने भी घाटे के बजट आए उन को हम ने पचाया और मैं आशा करता हूं कि यह घाटे का बजट भी हम पचाएंगे। इन घाटे के बजटों के माध्यम से ही हमने क्या क्या नहीं किया? हम ने नये नये कारखाने खोले, हम ने कृषि के उत्पादन में बढ़ोत्तरी की। आज जब हम पुराने जमाने के काश्तकार का चित्र अपने मस्तिष्क में लाते हैं तो ढलते सूर्य के लालिमा-युक्त क्षितिज की पृष्ठभूमि में लड़खड़ाते कदमों को लिए हुए, झुकी हुई कमर, साथ ही साथ हल अपने कन्धों पर रखे हुए एक मनुष्य का चित्र हमारे मस्तिष्क में उभर आता है। और आज जब हम उस काश्तकार का चित्र अपने मस्तिष्क में उठाना चाहते हैं तो हमें उस में सजगता दिखती है, चेतनता दिखती है, उस के कदमों में ताकत दिखाई देती है। आज के काश्तकार का नमूना पंजाब का काश्तकार है। पंजाब के काश्तकार को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने एक विशाल वक्षःस्थल वाला मानव दिखाई देता है। हमें मालूम पड़ता है कि एक सजग काश्तकार और एकसचेतन काश्तकार हमारे सामने खड़ा है। तो हम ने काश्तकारी में उन्नति की ओर जो शस्य श्यामलां मातरम् गीत हम गाते हैं उसे हमने चरितार्थ किया। इस से पहले पुराने जमाने में भिक्षां देहि, भिक्षां देहि का गीत जो हम गाया करते थे यह एक शर्मनाक बात भारत के लिए थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश स्वावलम्बी बने। इससे पहिले भी बजट घाटे के थे। लेकिन उस समय हम तात्कालिक फायदा उन बजटों से नहीं ले सके। आज हमें उम्मीद है कि घाटे का बजट रहते हुए भी हम यह प्रयत्न करेंगे कि नई क्षमताएं पैदा करें और उत्पादन ज्यादा बढ़ाए। लेकिन साथ ही साथ यह भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि केवल उत्पादन बढ़ाने से ही घाटे की पूर्ति हम नहीं कर सकेंगे हमें प्रशासनिक योग्यता लानी पड़ेगी। हमें मितव्ययिता लानी पड़ेगी। हमें जल्दी से जल्दी जो निर्णय करते हैं वह निर्णय लेने पड़ेंगे। जब हम यह तीनों बातें करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम इस घाटे

[श्री गंगा चरण दीक्षित]

के बजट के रहते हुए भी तरक्की करेंगे और हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा।

मैं एक दो मिनट मध्य प्रदेश के बारे में कह देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का विस्तार उस के अंदर पिछड़े वर्गों की अधिक संख्या, साथ ही साथ साधनों की बहुलता होते हुए भी उन के दोहन करने के लिए जो वित्तीय सहायता हमें केन्द्रीय सरकार से नहीं मिलती वह एक बड़ी शर्ममनाक बात मध्य प्रदेश के लिये है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े साधन हैं। उस का कोई अंचल आप देखें तो वह खनिज की सम्पदा से भरा हुआ मिलेगा। कोई उसका भाग देखें तो चावलों का भण्डार उसे कहा जाता है और साथ साथ गेहूं के उत्पादन में भी हम विश्व के अन्य किसी भी भाग के समकक्ष खड़े रह सकते हैं। हमारे पास वन-सम्पदा अधिक से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक और खाद्य और कृषि के विशेषज्ञ प्रोफेसर विस्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा वन सम्पदा है कि उस वन सम्पदा से 92 मिलियन घन मीटर औद्योगिक लकड़ी का हम उत्पादन कर सकते हैं। जब कि आज केवल 9 मिलियन घन मीटर वन सम्पदा का उपयोग किया जा रहा है। 92 मिलियन घन मीटर के बजाय केवल 9 मिलियन घन मीटर वन सम्पदा का उपयोग हो पाता है केवल इसलिए कि केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलती। मेरी प्रार्थना है वित्त मंत्री सहोदय से कि मध्य प्रदेश के विस्तार को देखते हुए, मध्य प्रदेश की वन-सम्पदा को देखते हुए, मध्य प्रदेश की खनिज की बहुलता को देखते हुए केन्द्रीय शासन की ओर से उस की अधिक से अधिक सहायता करने की कृपा करे।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के सिलसिले में कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह बात दुरुस्त है कि इस बजट में जो आउट लाइन दी गई है उसके सिलसिले में एक बात साफ है कि कोशिश की गई है कि हम समाज को बदलें। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आधे मन से कोई आदमी काम करे, बुझे हुए मन से कोई आदमी काम करे। इस बजट में समाज को बदलने की बातें, मोनोपली को कर्ब करने की बातें तो की गई हैं लेकिन वह सिर्फ आधे मन से या बुझे हुए मन से करने की बात-नजर आती है। आज हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि हम इस बजट को किस तरह से पास करते हैं। सवाल यह है कि आज हिन्दुस्तान के लोग चाहते क्या हैं? उस प्रेरणा को, उस नारे को जो इलेक्शन में हमने लगाया हिन्दुस्तान की जनता आज देखना चाहती है उस तरफ हम कदम उठाते है कि नहीं उठाते हैं। यह मैं मानता हूं कि इस तरफ कोशिश की गई है। लेकिन जो जो कदम उठाने की जरूरत है उस तरफ पूरी संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कि आमदनी बढ़ानी है। लेकिन हमारा बहुत सा रुपया जाया हो रहा है। जब तक आप इस मुल्क में मिक्सड एकोनामी सिस्टम रखेंगे, मुश्तर्का इक्तसादी सिस्टम रखेंगे तब तक पब्लिक सेक्टर कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पूरे दिल से, पूरी हिम्मत से कोशिश कर के हमें मोनोपली को कर्ब करना है। आज हम रे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि पब्लिक सेक्टर कामयाब नहीं हो रहे हैं जब कि प्राइवेट सेक्टर कामयाब हैं। क्यों? क्यों कि पब्लिक सेक्टर बेसिक इंडस्ट्री में जाता है और प्राइवेट सेक्टर कन्ज्यूमर्स इंडस्ट्री में जाता है। वह प्राफिट भी करता है, हम उसका नफा कमाने की इजाजत भी देते हैं, पूरा उसको कंट्रोल भी नहीं करते, उसको ब्लैक करने की इजाजत देते है, उसको फलने फूलने की इजाजत देते हैं और उसको यह भी इजाजत देते हैं कि

वह हमारे पब्लिक सेक्टर में आकर हमें सेबोटेज करे। इसको रोकने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। इस मुल्क में तब्दीली तब तक नहीं आ सकती जब तक आप पब्लिक सेक्टर को कन्ज्यूमर्स गुड्स में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को, मोनोपलीज़ को कर्ब नहीं करेंगे। आज हम हर बात को अवायड करते हैं। हम सोचते हैं कि इस मसले को टच करें या न करें। जैसे आज एक बड़ा सवाल है रूरल सेक्टर के अंदर बड़ी आमदनी वालों पर टैक्स लगाने का। फ्यूडल सिस्टम को हम सीलिंग के जरिए घटाना चाहते है, सीलिंग से वह बच निकलते हैं। ऐग्रीकल्चरल सिस्टम पर हम टैक्स नहीं लगाना चाहते, ट्रैक्टर पर टैक्स लगा कर उसकी पूर्त्ति करना चाहते हैं। आज हिन्दुस्तान की प्राबलम है प्राइवेट सेक्टर की मोनोपली, आज हिन्दुस्तान की प्राबलम है बैंड ऐडमिनिस्ट्रेशन, आज हिन्दुस्तान की प्राबलम है पब्लिक सेक्टर का प्राफिट में न चलना हिन्दुस्तान मे प्राबलम है बेकारी की, हिन्दुस्तान मे प्राबलम है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर सैक्टर में जो बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं, उन पर टैक्स लगाना चाहिये। इन तमाम बड़े बड़े मसलों के बारे में.....

अध्यक्ष महोदय : आप लंच के बाद अपनी स्पीच जारी रखें।

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch and four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the chair*].

GENERAL BUDGET, 1971-72—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

श्री सतपाल कपूर : डिप्टी स्पीकर साहब, इससे पहले मे कुछ बातें आपकी मार्फत कह चुका हूं। इस बजट से हम कोई बुनियादी तब्दीली नहीं कर सकते है। अगर इसी रफ्तार से, जैसे कि हम चल रहे हैं समाज बदलने की तरफ, हम चलें तो मुझे उम्मीद है कि हम कभी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच नहीं सकते हैं। आज जरूरत है समाज बदलने की। इस किस्म का बजट, इस किस्म का जज्बा, यह रफ्तार वेलफेयर स्टेट की तरफ तो ले जा सकती है लेकिन सोशलिस्ट स्टेट की तरफ, सोशलिज्म की तरफ हम इस तरह चल नहीं सकते है, बढ नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। यह ठीक है कि इस बजट में कुछ बातों की तरफ रौशनी डालने की कोशिश की गई है लेकिन इस बजट ने सरमायेदारों पर तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डाला लेकिन गरीब लोगों को नाराज जरूर किया हैं। तो जरूरत हैं समाज बदलने की और समाज इस रफ्तार से हम बदल नहीं सकते, उसके लिए कुछ बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। आज हमारा समाज जिस तरह से चल रहा है, हम बेकारी दूर करना चाहते हैं जोकि एक बहुत बड़ा मसला है लेकिन उसके लिए जितनी बड़ी स्पिरिट, जितनी बड़ी कोशिश जितनी हिम्मत करने की जरूरत है वह हम कर नहीं रहे हैं। हम इश्यूज को फेस नहीं करते बल्कि हाच-पाच करके, कनफ्यूज करके छुटकारा हासिल करने की तरफ हम बढ़ रहे है। यह तरीका चलने वाला नहीं है, इसको बदलना होगा। आज हमारे देश में हम चाहते है कि पब्लिक सेक्टर मजबूत हो लेकिन पब्लिक सेक्टर तो मजबूत होता नहीं बल्कि हमारे काम करने के ढंग से प्राइवेट सेक्टर मजबूत होता है और जहां जहां प्राइवेट सेक्टर को दिक्कत आती है उसके शेयर्स

[श्री सतपाल कपूर]

हम खरीद लेते हैं। अगर इसी ढंग से पब्लिक सेक्टर बनाना है तो पब्लिक सेक्टर, सोशलिस्ट समाज और सोशलिस्ट एकोनामी ये तीनों बातें बिल्ड होने वाली नहीं हैं, बनने वाली नहीं है, यह बात हमें समझ लेनी चाहिए।

एक सवाल यह है कि नये समाज को बनाने के लिए और बुनियादी तब्दीली करने के लिए क्या हमारा मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा हमें उस तरफ जाने में मदद देता है? मेरा अपना तजुर्बा है कि आज अगर गरीब के लिए आप कुछ करना चाहें तो उसमें जहां सरमायेदादार एक रुकावट है उससे एक बड़ी रुकावट यह एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी हैं और उनमें इस बात का जिक्र आया है कि आप डिले को किस तरह से दूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का समाज हम हिन्दुस्तान में बनाना चाहते हैं उस तरह का न तो हमारे यहां नक्शा है और न उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है। इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से आप इस मुल्क के अन्दर बुनियादी तब्दीली नहीं ला सकते। इस तरीके को बदलना पड़ेगा। आज अगर हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वह अफसरों का रवैया है। हर वह काम जो आप करवाना चाहते हैं गरीब के हक में वह नामुमकिन है और अमीर के हक में हर काम जो आप करवाना चाहते हैं गरीब के हक में वह नामुमकिन है और अमीर के हक में हर काम मुमकिन है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी थिंकिंग, उसकी वर्किंग, उसका ढंग और उसका रवैया सब अमीरों के हक में है और गरीबों के खिलाफ है। इस ढंग से हम मुल्क के लोगों को कोई आराम नहीं दे सकते, इस मुल्क में बुनियादी तब्दीलियां नहीं ला सकते। गरीबी हटाने की बात आप कह सकते हैं और लोगों से वोट ले सकते हैं लेकिन आप गरीबी हटा नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए।

आज कहा जाता है कि पब्लिक सैक्टर में घाटा है और प्राइवेट सेक्टर में मुनाफा है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर में तो हम इंक्वायरी करते नहीं कि किस प्रकार से वे मुनाफा कमाते है। हमारे पास पब्लिक सेक्टर में बेसिक इंडस्ट्रीज है और प्राइवेट सेक्टर में कन्ज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, उसमें वे किस किस्म की घपलेबाजी करते है उसकी कोई चेकिंग आज हमारे पास नहीं है। हमने कुछ कंट्रोल लगाया है लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि एक जुडिशिवल कमीशन मुकर्रर किया जाये जो कि प्राइवेट सेक्टर के काम करने ढंग को इंक्वायर करे, जो इस बात को देखे कि प्राइवेट सैक्टर टैक्स को किस तरह से इवेट करता है, किस तरह से वह ब्लैक-मार्केटिंग करता है, प्राइवेट सेक्टर गरीबी को किस तरह से बढ़ाता है, ब्लैक मनी किस तरह से पैदा करता है और किस तरह से इस समाज में तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। आज इस तरह का कमीशन बनाने की जरूरत है। मैं समझता हूं सरकार इस बात की तरफ ध्यान देगी।

आज एक बात यह कही जाती है कि समाज को बदलना बहुत मुश्किल है, गरीबी हटाना बहुत मुश्किल है और पब्लिक सेक्टर को चलाना बहुत मुश्किल है।... (व्यवधान)... यह सब कुछ मुश्किल काम है क्यों कि हमारे विधान में कुछ कमजोरियां हैं। अगर आप समाज बदलना चाहते है तो इस मौजूदा विधान से समाज में बुनियादी तबदीलियां नहीं ला सकते, यह मैं मानता हूं। तो समाज में बुनियादी तबदीली लाने के लिए,

गरीब की झोंपड़ी में आराम पहुंचाने के लिए अगर विधान बदलने की जरूरत पड़े तो उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस तरफ़ हमें ध्यान देना चाहिये। मेरा यकीन है कि जब तक आप मौजूदा विधान के ढांचे को नहीं बदलते तब तक आप बुनियादी तबदीलियां नहीं ला सकते। सरकार को उस उस तरफ़ ध्यान देना चाहिए।

यह ठीक है कि इस बजट में कुछ गलत टैक्स भी लगाये गये हैं। मिसाल के तौर पर मैदे पर और सिगरेट पर टैक्स लगाया गया। क्या ही अच्छा होता अगर आप रुपये, डेढ़ रुपये तक की सिगरेट को छोड़ देते। हां, जो लोग इंडिया किंग और कैप्सटन पीते हैं उन पर टैक्स लग जाता तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं होता। आप टैक्स लगाते जो क्युटिक्योरा, पीयर्स सोप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गरीब आदमी भी जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उन पर भी आपने टैक्स लगा दिया। फिर कहें कि हम बड़े आदमी पर टैक्स लगाये है इससे कंट्राडिक्शन पैदा होता है, कोई जस्टिफिकेशन नही है। मिट्टी के तेल का आपने बजट में जिक्र नहीं किया। लेकिन उस पर दूसरे ढंग से ऐडमिनिस्ट्रेशन टैक्स ले आया।

अब मैं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जो पंजाब में है उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पंजाब में बहुत तरक्की हुई हैं। ठीक है। पजाब की तरक्की बिड़ला, टाटा की वजह से नहीं हुई, न आपके पब्लिक सैक्टर के कारखानों से हुई है, न पंजाब में बड़े बड़े महाराजा ने रुपया लगाया, बल्कि वहां लोगों ने खुद मेहनत की है और हिम्मत करके इंडस्ट्री में आये हैं। मिस्त्री और किसान का लड़का शहर में आया उसने मेहनत की तो एक कज्यूमर इंडस्ट्री बनाने में कामयाब हो गया। अब आप टैक्स उस पर लगा रहे हैं जो 5,000 रु० की मशीनरी अपने घर में लगा कर बैठा हैं। आपको उनको ऐग्जैम्पशन देना चाहिये। आपको कहना चाहिये कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में जो ढाई लाख से ऊपरी की मशीनरी लगां रहां है उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन ऐसा न करके जो आदमी 20 हजार रु० की मशीनरी घर में लगाये बैठा है उसको टैक्स करते हैं।

लोहे का कोटा लुधियाना में आम मिस्त्री को नहीं मिलता है। उनको लोहा 1800 रु० के भाव से ही मिलता है, जबकि बड़े बड़े सरमायेदारों को कंट्रोल रेट से मिलता है। आज कोटे का तरीका ऐसा बन गया है कि छोटा आदमी ब्लैक में माल लेता है और बड़े आदमी को सरकारी रेट पर मिलता है। इन सब बातों की तरफ में उम्मीद करता हूं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ध्यान देंगे तथा जो गरीबों को दुख देने वाले टैक्सेज हैं उनको वापस लेंगे।

श्रीमती सहोदराबाई राय (सागर): उपाध्यक्ष जी, बड़े भाग्य की बात है कि तीन दिन के बाद आपने हमें बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसका मैं स्वागत करती हूं और हृदय से धन्यवाद देती हूं कि जो टैक्स लगाये गये हैं वे बहुत अच्छे ढंग से और सोच समझ कर लगाये गये हैं। क्योंकि देश में गरीबी बहुत ज्यादा है इसलिये गरीबों की उन्नति के लिये पैसा सरकार को चाहिए और उसका प्रबन्ध वित्त मंत्री जी ने सुन्दर ढंग से किया ताकि गरीबों पर ज्यादा टैक्स न पड़े और उनको ज्यादा पैसा मिले अपनी उन्नति के कामों के लिये, और बड़े लोगों पर ज्यादा टैक्स लगे।

सब प्रनतों के माननीय सदस्य बोल चुके हैं, कोई ऐसी चीज बकाया नहीं है जिस पर कि मैं बोलूं। हमारे पंजाब के माननीय सदस्य

[श्रीमती सहोराबाई राय]

से कहा कि पंजाब में काफी खुशहाली है, सरकार का कुछ भी पैसा नहीं लगा। लेकिन मेरा कहना है कि जितना पैसा सरकार ने लगाया है, या दिया है, वह सब पंजाब में ही तो लगा है। वहां अच्छे साधन हैं, कुंए हैं, सब कुछ पैसा आप ही लड़ कर ले गए। इसीलिये दूसरे प्रान्तों की उन्नति नही हुई। मेरा निवेदन हैं कि पंजाब एरिया में अब कुछ भी पैसा न लगाया जाये। पैसा वहाँ लगाया जाय जहां कि नहीं के बराबर काम हुआ है। पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र काफी धनी प्रान्त हैं। सरकार को पैसा उन प्रान्तो में लगाना चाहिये जहां न तो बिजली है, न पीने का पानी है, न सिंचाई के साधन हैं और जहां किसानी करने वाले किसान रहते हैं। ऐसी जगह पैसा लगाने की जरूरत है जिस से खेती हो, वहां के लोग अपनी अपनी उन्नति कर सकें। जब हम अपने प्रान्त के मुख्य मंत्रीं से बात करते हैं, अभी पंचमढ़ी में बैठक हुई थी उस में कहा था कि जितना केन्द्र से हम पैसा लायेंगे उतना काम प्रान्त मे प्रान्तीय सरकार कर देगी क्यों कि प्रान्तीय सरकार के पास पैसा नहीं है। यह वहा के मुख्य मंत्री का जवाब था।

हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रान्त है, डकैत एरिया है जिस का कारण मेरी राय में यह है कि पहले वहां राजे महाराजे, यानी बुंदेले थे, उनकी जागीरें चली गयीं, अब कोई जीवन का सहारा नहीं है इसलिये वह डाका डालते हैं। आप को ऐसी जगह पर उद्योग धंधे खोलने चाहियें, रेलवे लाइनें खोलिये जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले। एक मिलिटरी की टुकड़ी खोलिये जिसमें वहीं के लोग भर्ती हो सकें। आज वहां दिन दहाड़े डकैतीं पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि भारत में जैसे कोई राज ही नहीं है। दिन दहाड़े औरतों के गहने उतार ले जाते हैं, व्यापारियों को मोटर से उतार लेते हैं और लाख,दो लाख रुपया उन को छोड़ने की एवज में मांगते हैं। वहां के लोग डर के मारे सो नहीं पाते और शहरों की तरफ़ भागते हैं। जनता बड़ी परेशान है। इसलिये मेरा कहना है कि आप ऐसे कदम उठायें जिनसे वहां की इस समस्या का समाधान हो सके। वहां फ़ौज लगायी जाय। जब आप एक डकैत एरिया का बन्दोबस्त नही कर सकते तो भारत की आजादी की रक्षा कैसे कर सकते हैं। हमारे वहां महिलाओं को बड़ी दिक्कत है। लोग तो डरके मारे जंगल मे भाग जाते है लेकिन महिलाये बेचारी कहां भागें। उनको गोली से मरना पडता है। सागर, शाहगढ़, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, मारैना के बीच में ज्यादा डकैतियां पड़ रही हैं, वहां की जनता परेशान है। आप तो बंगलों मे आराम से सोते हैं आपको वहां की कठिनाइयों का क्या आभास हो सकता है। औरतो की साड़ियां, गहने, जेवर ले जाते हैं और बाद में गोली से भी मार देते हैं। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि बुंदेलखंड में फ़ौजी टुकड़ी खोली जाय,साथ ही एक रेलवे लाइन सागर से शाहगढ़ छतरपुर, पन्ना से टीकमगढ़ होते हुए लायी जाय जिससे लोगों को काम मिले। वह ऐरिया बिल्कुल सूखा है, वहां की रेतीली जमीन है जैसी कि राजस्थान में है। वहां के लोग महुआ पर गुजर करते हैं। इसलिये पंजाब, हरियाणा में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा मध्य प्रदेश में लगाना चाहिये जिस से वहां का विकास हो। अभी पंजाब के माननीय सदस्य ने कहा कि हम खुद उन्नति के काम करते हैं, सरकार से कोई सहायता नहीं लेते। लेकिन मेरा कहना है कि जितना पंजाब ने ले लिया है उतना किसी प्रान्त ने नहीं लिया। जितने पंजाबी लोग हैं सारे मध्य प्रदेश में भरे

हुए हैं। जंगल, कोयला और मोटर का सारा रोज़गार उन के हाथ में है। सब पैसा कमा कर वह ले जाते हैं। आप भारत में कहीं भी चले जाइये आप को दो चीजें सब जगह मिलेंगी। एक आलू और एक पंजाबी आपको सब जगह मिलेंगे। इसलिये में कहूंगी कि इन को सहायता की आवश्यकता नहीं हैं। पैसा वहां लगाया जाय जहां जनता को कष्ट है। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जाता है। वित्त मंत्री भी दबाव और दोस्ती के कारण काम करते हैं और जो हम लोग हिन्दी बोलने वाले हैं उनके काम पड़े ही रहते हैं। इसलिये ऐसे क्षेत्रों में पैसा लगाना चाहिये जहां खेती ज्यादा है। वहां ट्रैक्टर बनाने चाहिये। हमारे वहां भूसा ज्यादा होता है वहां पुट्ठे का कारखाना खोलना चाहिये क्यों कि सागर और दमोह में गल्ला ज्यादा होता है। वहां के लोगों को सिचाई, बिजली और ट्रैक्टर के साधन मिलने चाहिये। अगर आप ही पैसा नहीं देंगे तो प्रान्ती सरकार कहां से पैसा लायेगी। उसके साधन तो सीमित हैं।

बुंदेलखंड, जो देशभक्तों का स्थल रहा है, रानी झांसी जहां हुई, अंग्रेजों के जमाने में वहां कोई उन्नति के काम नहीं हुए। इधर 23 वर्ष से जब से देश आजाद हुआ, प्रान्त में जरा कुछ काम हुआ है, लेकिन वह काफ़ी नहीं है और प्रान्तों की तुलना में। वैसे हरिजनों, आदिवासियों की स्थिति अच्छी हैं। लेकिन शहर की तरफ ज्यादा है, देहात की तरफ कम है। वहां ब्राम्हण, ठाकुर लोग ईर्ष्या करते हैं, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन हम कहते हैं कि गरीब हैं बढ़ने दो। जमीन जब भूमिहीनों में बांटी जाती है तो ब्राम्हण, ठाकुर, हम से जब क्षेत्र में जाते हैं तो यही कहते हैं कि आपका भाग्य बड़ा अच्छा है क्यों कि वजीफा मिलता हैं, पढ़ाई लिखाई में, सबमें आपको मौका मिलता है। हमारे पास जमीन नहीं है, वह हमको दिलाई जाये। यह कानून भी होना चहिये कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन मिलनी चाहिये, दूसरी सुविधायें मिलनी चाहिये और केन्द्र से रुपया मिलना चाहिये। बैलों के लिये उनको तकावी मिलनी चाहिये। जब तक यह सुविधायें नहीं मिलतीं, हमारे हरिजन और आदिवासी भाई उन्नति नहीं कर सकते। यह ठीक है कि उनको पैसा मिलता है, लेकिन ठीक ढंग से नहीं मिलता। न जाने बीच में वह किसके पास चला जाता है। सरकार को इसकी एन्क्वारी करवानी चाहिये और ऐसा उपाय करना चाहिये कि देहात के लोगों को पूरा पैसा मिले। हम लोगों को जमीदार परेशान करता है, पटवारी परेशान करता है। अगर एक हजार रुपया मिलता है तो जब तक उनको 200 रु० न दिया जाये तब तक वह हमको पैसा नहीं मिलने देते हैं। अगर हम सिफारिश ले कर जाते हैं तो वह कहते हैं कि हम लोग उनके काम में रोड़ा अटकाते है। सारा लेन देन प्राइवेटली हो जाता है, गवर्नमेंट को कुछ पता नही चलता। आप देहातों में चल कर देखिये कि वहां क्या हाल हो रहा है। वहां कोई तरक्की नहीं हो रही है सिवा इसके कि बेईमानी और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जब हम लोग पुलिस से कहते हैं तो वह लोग कहते हैं कि हम क्या करें। हमारी इतनी कम तन्ख्वाह है तो हम गुजर कैसे करें? लोग बड़ी मुश्किल से उनसे बच पाते हैं।

हमारे यहां सागर यूनिवर्सिटी है। वहां कोई मेडिकल कालेज नहीं है। वहां पर आपको एक मेडिकल कालेज खोलना चाहिये, साथ ही वहां की यूनिवर्सिटी के लिये जो रुपया दिया जाता है उसको और बढ़ाना चाहिये। वहां के लड़कों और लड़कियों ने हमें काफी वोट दिये

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

हैं। वहां पर जन कैंप की महारानी ग्वालियर ने हमारे लिये बड़ी परेशानी पैदा करने की, कोशिश की खूब रुपया खर्च किया, लेकिन वहां की जनता ने उनका समर्थन नहीं किया और वहां पर जन संघ का कबाड़ा हो गया। हमारे श्री बाजपेयी हंस रहे है। मैं कहती हूं कि आज वह किसी दूसरी जगह से खड़े होकर देख लें, वह कभी भी नही जीत सकेंगे। मैं कहती हूं कि हमारी बात आप को सुननी चाहिये। आपने जो 25 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिये रक्खा है उसको लड़कियों की शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाये। आज हजारों लड़कियां पढ़ कर निकलती है। उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिये। आज बहुत से हरिजन लड़कियां पढ़ लिख कर बेकार घूम रही हैं, उनको काम मिलना चाहिये। हरिजन लड़कियों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिये और बिना पैसे उनको शिक्षा संस्थाओ में भरती करना चाहिये।

कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यहां पर जन्म टैक्स लगना चाहिये। लेकिन जो गरीब हरिजन और आदिवासी लोग हैं, वह तो कोई टैक्स दे नहीं सकते। कई माननीय सदस्य करोड़पति हैं, वह लोग ज्यादा दे सकते हैं। अगर उनसे ही लिया जाय तो यह कोई बुरी बात नहीं है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि श्रंगार की वस्तुओं पर अगर टैक्स लगना चाहिये। मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं के श्रंगार पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो हमें बड़ी खुशी है। अगर महिलाओं के जरिये यह टैक्स मिलता है और उससे देश का भला होता है तो महिलायें यह टैक्स देने के लिए तैयार हैं और मर्दों के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चलने के लिये तैयार हैं।

बंगला देश से जो शरणार्थी आये हैं उनके लिए ग्वालियर, मोरैना और चम्बल घाटी में लाखों एकड़ भूमि पड़ी है। उसको ट्रैक्टरों से जुतवा कर इन शरणार्थियों को वहां बसा दिया जाये ताकि उनको अपने कष्टों से निस्तार मिले।

इसके बाद में यह कहना चाहती हूं कि कि 1945-46 में नोआखाली में जब झगड़ा हुआ था हिन्दू मुसलमानों का तब वहां महात्मा गांधी गये थे, ठक्कर बापा गये थे, पंडित जी गये थे, सुचेता कृपालानी गई थीं। वह लोग जो मुसलमान हैं वहां कहते थे कि :

काब मे बीड़ी, मुंह में पान,
लड़ के लेंगे पाकिस्तान।
हिन्दुओ से लेंगे पाकिस्तान,
खून से लेंगे पाकिस्तान।

वहां पर लाखों हिन्दू मारे गये थे। उनके मकान जला दिये गये। जो कुछ वहां पर उन्होने किया था हिन्दुओं के साथ से वही आज उनके साथ हो रहा है। वहां पर एक जगह पर 700 हिन्दुओं की लाशें निकली थी महात्मा जी के सामने वहां। पर जो कुछ भी हो रहा है वह उस समय हमारे हिन्दुओं के कत्ल के कारण हो रहा है। इस लिये मंत्री महोदय को सचेत रहना है। उन लोगों का कोई विश्वास नहीं है कि कब वे उलट पड़ें। उन के ऊपर पूरी निगाह रखनी चाहिये। बित्त मंत्री जी ज्यादा समय उनको न दें, जल्दी से जल्दी उनको उठायें क्योंकि इसमें बड़ा खतरा है। यह एक राजनीतिक चाल है। अगर वह उनसे हमारी रक्षा नहीं करेंगे और जल्दी नहीं करेंगे तो यह खतरा है कि वह हिन्दुस्तान के लिये नुकसान पैदा करने वाले है। एक दिन आने वाला है जब हिन्दुस्तान में पूरा पाकिस्तान मिल कर रहेगा क्योंकि वहां की जनता परेशान है। सारा हिन्दुस्तान एक हो जायेगा और पाकिस्तान नहीं रहेगा।

SHRIMATI MUKUL BANERJEE (New Delhi) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I support the budget proposals and I feel that this is a very progressive budget and also it is fully to the tune of our declared policy of a socialist transformation. I do not agree with those members who say that we gave the slogan of *Garibi Hatao* and now we are going away from it, because at that time when our beloved Prime Minister gave the slogan of *Garibi Hatao*, we did not have this national calamity of Bangla Desh affecting our nation. As our Prime Minister has said this is internal affair of India, and I fully believe, and everybody knows, how it is taxing our country and what a terrible burden it is on our country.

We have always seen that our people are not lagging behind in their support whenever any national calamity comes ; we have seen that in many cases of the contribution of our poor people has been far more than that of the richer people. So, when such a burden has come, we know that our poor people will also be ready to help and support the cause.

There is another aspect which arises. In a developing economy, the tax always rises. But I would only like to say that there is so much of unemployment in our country. For that also, to solve that, we need so much money ; the money will have to come. If we do not get more and more money, if we do not have more and more money to solve this unemployment problem, actually the educated unemployed will be very angry as they are getting angry and they are getting restless. Unless we solve their problems too, unless we increase some of the burden on some of the people, we shall not be able to satisfy them. Rather, the problems will increase and that may hit the basic stability of our country. So, some taxes will have to be raised. Why should we not take the help of the poor people for helping and co-operating in improving the economy of the country? The poor people are not backing away from it.

I would now like to give a few suggestions to the hon. Finance Minister for his consideration. One is, I feel that the tax on bread should be removed, because even the poor people do not stay only in the villages. There are many, many poor people in the cities and small towns also, and in small towns and cities the poor people cannot buy coal or even wood for preparing their *chappathies*. So, they sometimes find bread cheaper. The low income group people also, especially when both husband and wife are working for a living, they do not find time to prepare *chappathies* and that creates a lot of difficulties. Therefore, I feel that it would be better if the hon. Finance Minister considers this and removes the tax on maida.

Then my second point is this. I would request the hon. Finance Minister to reconsider the tax on petrol. I understand that the International prices of petrol have increased and the prices of petrol here also will increase. But I do not mind if you tax the private cars-owners or the private scooter-owners, the private users. But I do certainly feel that it would be too much on the people because in the remote places like Himachal Pradesh or Manipur and other places, there is no train service and the people can travel only by buses, and on those conveyances also the charges will be too much if the petrol charges go high up.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : Those buses use diesel and not petrol.

SHRIMATI MUKUL BANERJEE : Still, the people who ply taxis and scooters in the cities are not rich people. So if you have to increase the tax on petrol then you will have to allow the owners of taxis and scooters to raise their fares proportionately. Otherwise, they will lose.

Then I come to the impost on pressure cookers. You may levy a duty, or increase the existing one, on lipsticks and cosmetics. But you should not impose any duty on pressure cookers which is used by even low income group people. Especially when the husband and wife are working the cooking has to be done in a hurry and so people are forced to use pressure-cookers. So, this aspect has to be considered.

[Shrimati Mukul Banerjee]

Then, coming to ready-made garments, I would like to clear some misunderstanding. Some of my friends were saying that all ready-made garments have been taxed. It is not so. I am verey happy to know from the hon. Finance Minister that tax has not been imposed on all ready-made garments but only on branded qualities. The branded qualities are used only by the rich and not by the poor.

Coming to the tax on soap, a majority of the people in the villages do not use toilet soaps. The use household soaps both for bath and for washing their clothes. Further, there is no increase in the rate of tax on laundry soap.

I am very happy that the hon. Finance Minister has shown concern about the health of the smokers. Of course, it has affected my household also, because my husband is a smoker. I would request the Finance Minister to show the same concern about alcoholic drinks also and tax them still further.

Finally, I would like to say that nothing has been done to improve the plight of the Delhi school teachers with the result that they feel frustrated. Now there is a lot of disparity between the pay scales of the principals and the post-graduate teachers even though their qualifications are the same. While the basic pay of a principal starts from Rs. 700 the maximnm salary of a post-graduate teacher is only Rs. 600. In other service conditions also there is a lot of disparity. I would request the Finance Minister to give a little more money for the amelioration of the condition of the Delhi school teachers so that these discriminations can be removed and the teachers can feel happy so that our future generations will get better education.

With these few suggestions, I would like to congratulate the Finance Minister for having presented this budget.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्यावधि चुनावों में भारी भरकम बहुमत प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्री महोदय ने एक अंतरिम बजट पेश किया था और उसमें जो कुछ कहा था उसको मैं उनके शब्दों में ही उद्धत करना चाहता हूं :

> "हम विकास की गति तीव्र करेंगे और समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।"

वित्त मंत्री ने आगे चल कर यह भी कहा था। मैं उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं :

> "अब हम गरीबी और अन्याय के विरुद्ध एक नई लड़ाई लड रहे हैं। मुझे कोई सन्देह नही है कि भारत की जनता एक बार फिर विजयी होगी और इस महान और प्रजातंत्रीय देश में शीघ्र ही सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता का नया अरुणोदय होगा।"

वित्त मंत्री के इन शब्दों से और इन शब्दों में निहित भावनाओं से किसी का मतभेद नहीं हो सकता। किन्तु जब हम उनके नए बजट को इस कसौटी पर कसते हैं तो वह उचित सिद्ध नहीं होता। नए बजट में विकास की दर बढ़ेगी इसका कोई आश्वासन नही दिया गया है। कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी इसके सम्बन्ध में भी कोई ठोस उपाय या योजना नहीं की गई है। अब यह कहा जा रहा है कि यह बजट समाजवादी नहीं है क्योंकि एक बजट से समाजवाद नहीं आ सकता। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबी हटाने के लिए हमारे वित्त मंत्री के पास कोई जादू का डंडा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह बजट विकास विरोधी बजट है। यह बजट बचत को प्रोत्साहन नहीं देता। यह बजट विषमता कम नहीं करता और न यह बजट विकास की दर बढ़ाने के लिए जिन

साधनों को जुटाया जा सकता है उन साधनों को जुटाने का साहसपूर्ण प्रयत्न ही करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि हर बजट में योजना के नाम पर अधिक रुपया रखने की बात कही जाती है। इस बजट में भी वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि हम 155 करोड़ रुपया इस साल की चौथी योजना के लिए अधिक रख रहे हैं। जब वित्त मंत्री महोदय ने यह बात कही तो अनेक माननीय सदस्यों ने तालियां बजाईं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना की कसौटी, योजना की सफलता या उसके लक्ष्यों की प्राप्ति केवल उसके लिए रुपया रखने तक ही सीमित है? आप अगर अंतरिम बजट को देखें और वित्त मंत्री महोदय ने एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम जो रखा था उसको उठा कर देखें तो आपको पढ़ कर ताज्जुब होगा कि पिछले बजट में हमने अलग अलग मदों के लिए योजना के निमित्त कई जगह रुपया रखा था लेकिन वह रुपया खर्च नहीं हुआ। टोटल प्लान एक्सपेंडीचर पब्लिक सैक्टर प्लांज 2122 करोड़ था और खर्च हुआ 1953 करोड़। शार्टफाल था 169 करोड़। रुपया रखा तो गया लेकिन खर्च नहीं किया जा सका। जो रुपया रखा गया और जिन मदों के लिए रखा गया और जो खर्च नहीं हो सका, उसको देख कर आपको ताज्जुब होगा।

रूरल वर्कस (ड्राउड एरिया) के लिए 25 करोड़ रुपया रखा गया था जबकि केवल छः करोड़ खर्च हुआ और उन्नीस करोड़ बिना खर्च किये हुए पड़ा है। आज देश के अनेक भागों में अकाल की स्थिति है। उसके लिए संसद ने प्रावधान किया था। लेकिन यह शासन तंत्र इतना निकम्मा है कि वह उस रुपये का लाभ नहीं उठा सका, उसको व्यय नहीं कर सका। फिर जब बजट पेश किया जाता है तो अधिक रुपया मांगा जाता है। फर्टिलाइज़र की देश में कमी है। फर्टिलाइज़र का हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र किसानों को महंगा बेचा जा रहा है। लेकिन फर्टिलाइज़र के लिए हमने 27 करोड़ रुपया रखा था। उसमें से उन्नीस करोड खर्च हुआ और आठ करोड़ बच गया। गवर्नमेंट कम्पनीज़ एंड कारपोरेशंज़ 241 करोड़ खर्च करने का प्लान किया था लेकिन 191 करोड़ खर्च किया और पचास करोड़ बच गया। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि खर्च में कमी होने के कारण क्या हैं? इस बार भी जो 155 करोड़ रुपया रखा गया है उसमें से वित्त मंत्री महोदय ने हवाला दिया है कि हम अन्न की वसूली के लिए 18 करोड़ रुपया रख रहे हैं। अगर वह पिछले हिसाब को उठा कर देखें तो उनको पता चलेगा कि फूड कारपोरेशन के लिए जितना रुपया रखा गया था वह खर्च नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि अन्न की वसूली फूड कारपोरेशन के अलावा कौन करने वाला है? अगर राज्य सरकारें कर रही हैं तो उसके लिए तो केन्द्र के बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से वह रकम फूड करपोरेशन की मदद में जाएगी और फूड कारपोरेशन पिछले साल का रुपया खर्च नहीं कर सका है।

"गरीबी हटाओ" का नारा लगा था। यह तो कोई नहीं कहता कि एक बजट से गरीबी हट जायेगी। लेकिन अगर गरीबी हटे नहीं, तो कम से कम घंटे तो जरूर। जो कर लगाये गये हैं, क्या वे आम आदमी पर पड़े हुए बोझ को बढ़ाने वाले नहीं हैं? वित्त मंत्री महोदय से पहले रेल मंत्री ने बजट पेश किया और किराये की दर में वृद्धि कर दी—तीसरे दर्जे में सफर करने वालों पर 11 करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया और माल-भाड़े की दर में बढ़ौतरी कर दी। क्या

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उसका असर चीजों के मूल्यों पर नहीं पड़ेगा ? और उसके बाद पैट्रोल का दाम बढ़ाया गया है। अभी वित्त मंत्री कह रहे थे कि टैक्सी और स्कूटर चलाने वालों को अधिक दाम मिलेंगे। लेकिन वे अधिक दाम किसकी जेब में से जायेंगे ? जो टैक्सी में बैठते हैं, उनकी जेब में से। और ध्यान रखिये कि अगर टैक्सी में बैठने का किराया बढ़ेगा, तो टैक्सी में बैठने वालों की संख्या भी प्रभावित होगी, जिसका घाटा आखिर में टैक्सी चलाने वालों को भी उठाना पड़ेगा। अगर परिवहन महंगा होगा—डीज़ल के दाम भी बढ़े हैं—तो अन्ततोगत्वा आम आदमी पर जा कर बोझा पड़ेगा। क्या आम आदमी बोझा उठाने की स्थिति में है ?

इस बजट के द्वारा हम ने आम आदमी को कौन सा उत्साह का संदेश दिया है ? विषमता घटाने के लिए कौनसा कदम उठाया हैं ? जो दुर्बल वर्ग हैं, उनको राहत देने के लिए कौनसी प्रभावी उपाय-योजना की है ?

वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं अपने अन्तरिम बजट भाषण में चिन्ता प्रकट की थी कि मूल्य-वृद्धि हो रही है। और यह विचित्र बात है कि अन्न की पैदावार में वृद्धि होने के बाद भी मूल्य-वृद्धि हो रही है। मूल्य-वृद्धि के जो कारण पिछले साल थे, वे अब भी लागू हैं। गन्ने को छोड़कर और व्यावसायिक फसलों की कमी है। उसका परिणाम मूल्यों पर पड़ेगा। वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में जो कर-प्रस्ताव रखे हैं, उन सब का असर कुल मिलाकर यह होने वाला है कि 8 फ़सदी से लेकर 10 फीसदी तक चीजों के दाम बढ़ेंगे। हम एक ऐसे खुले बाज़ार की स्थिति में रह रहे हैं, जिसमें भले ही वित्त मंत्री कहें कि हम आधा पैसा दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वह उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते पांच नये पैसे में बदल जाता है।

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : माननीय सदस्य मूल्य-वृद्धि की बात कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मंडियों में जनसंघ के कर्मठ कार्यकर्ता और नियुक्त परचेज़ एजेन्ट किसानों को परेशान कर रहे हैं। उनके अनाज को सही दाम पर न खरीद कर दाम गिरा कर ख़रीदते हैं और उसी को फिर ऊंचे मूल्य पर सरकार को बेच देते हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बेतुकी बात का क्या जवाब दूं ? यह क्या बकवास कर रहे हैं ? यहां मैं कटघरे में नहीं खड़ा हूं, यह सरकार कटघरे मे खड़ी है। अगर जनसंघ के कार्यकर्ता गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन पर मुकदमा चलाया जाये। (व्यवधान) माननीय सदस्य को पता नहीं है कि यह बजट पर बहस हो रही है—जनसंघ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सवाल नहीं है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता दूध के धुले हैं ? मैं अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मामले पर भी आने वाला हूं।

श्री हरी सिंह : माननीय सदस्य बजट के खिलाफ आन्दोलन कर सकते हैं, लेकिन मंडी व्यापारियों से सरकार द्वारा नियत दामों को किसानों को देने के लिए नहीं कह सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहली बार यहां आये हैं। आप उनको जरा मना कीजिए। मुझे इस तरह की टोका-टोकी की आदत नहीं है। जनसंघ के कार्यकर्ता क्या करते हैं, यह सदन इस पर विचार करने के लिए नहीं है। (व्यवधान) यह किसानों के प्रतिनिधि हैं। ये बेतुकी और बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। यह क्या तरीका

है? अगर इनको सभ्यता का शिक्षण नहीं मिला है, तो इन्हें सभ्यता सीखनी चाहिए।

श्री हरी सिंह : सत्य कहना सभ्यता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनसंघ के कार्यकर्ता क्या करते हैं, यह सवाल नहीं है। वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, यह सवाल है। हमारे हाथ में सरकार नहीं है। सरकार इन लोगों के हाथ में है। इनमें सुनने का धैर्य भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इन्होंने बीच में मेरी गाड़ी पटरी पर से उतारने की कोशिश की।

इस बजट में 170 करोड़ रुपये के टैक्स नहीं लगे है, 220 करोड़ रुपये के टैक्स लगे हैं। अगर राज्यों का भी हिस्सा शामिल कर लिया जाये, तो 286 करोड़ रुपये के लगभग नया भार डाला गया है। वित्त मंत्री यह स्वीकार करेंगे कि चीनी आक्रमण के बाद के वर्ष को छोड़कर इतना बड़ा बोझ कभी नहीं लादा गया है। इतना बड़ा बोझ लादने का परिणाम अगर यह होता कि विकास की दर बढ़ती, हर एक सक्षम व्यक्ति के लिए रोजगार का प्रबन्ध होता, उपेक्षित वर्ग और उपेक्षित क्षेत्र अधिक गति से विकासशील हो सकते, तो फिर आम आदमी पर बोझ डाल कर भी स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए होने वाले प्रयत्न का समर्थन किया जा सकता था। लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। इस बजट से कौन खुश हैं? बड़े उद्योगपति खुश हैं, जिनके कार्पोरेट सैक्टर को स्पर्श नहीं किया गया है। इस बजट से बड़े किसान खुश हैं, जिनके प्रतिनिधि सत्तारूढ़ दल में बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं और जिनको हाथ लगाने का वित्त मंत्री महोदय ने साहस नहीं दिखाया है।

श्री के. एन. तिवारी (बेतिया) : यह बात नहीं है। उनको भी हाथ लगाया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बजट से मुनाफाख़ोर खुश हैं, जिन्हें उपभोक्ताओं से अधिक दाम लेने का अवसर मिलेगा। और इस बजट से असंतुष्ट हैं मध्यम वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, बंधी बंधाई तन्ख्वाह पाने वाले लोग, जिन पर बोझ बढ़ा है, जिन के लिए मूल्य-वृद्धि एक भयंकर संकट के रूप में आयेगी।

लेकिन सरकार भी उस संकट से बच नहीं सकेगी। महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग हो रही है। इन्डेक्स 225 बताया जा रहा है। 228 होते ही—दस पायंट बढ़ने पर महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ेगा। केन्द्र में महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तो राज्यों के कर्मचारी चुप नहीं रहेंगे। यह मांग ज़ोर पकड़ने वाली है कि महंगाई भत्ते में समानता होनी चाहिए, चाहे केन्द्र के कर्मचारी हों और चाहे राज्य के। और फिर एक विषम चक्र चलेगा, जिस में से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है।

यह कहा जा सकता है कि आखिर हम साधन कहां से जुटायें। और बजट की कोई भी आलोचना तब तक सार्थक नहीं होगी, अगर हम वैकल्पिक संसाधनों का सुझाव नहीं दे सकते। इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए कि क्या इम्पोर्ट लाइसेन्सों को नीलाम नहीं किया जा सकता है और यदि नीलाम करना उपयुक्त नहीं है, तो आज इम्पोर्ट लाइसेन्सों की बाज़ार में जो कीमत है, क्या उन्हें उस कीमत पर लोगों को बेचा जा सकता है। वित्त मंत्री महोदय इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इम्पोर्ट लाइसेन्स में मुनाफे का मार्जिन बहुत ज्यादा है। कुछ वस्तुओं के

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

आयात के लाइसेन्स दो सौ, तीन सौ गुणा ज्यादा कीमत पर बाजार में बिक रहे हैं। जो वास्तविक उपयोगकर्ता है, वे ऊंचे दाम पर कच्चा माल खरीदते हैं। बीच के लोग मुनाफा बना रहे हैं। यह मुनाफा सरकार के खज़ाने में क्यों नहीं आना चाहिए? ऊंची से ऊंची बोली बोलने वाले को इम्पोर्ट लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाना चाहिए?

जैसा कि मैं ने हवाला दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ग के पास समृद्धि—आ रही है, जिस ने खेती के नये तरीकों का उपयोग किया है, जिस के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है। जो बड़ा किसान है, वह राष्ट्रीय समृद्धि में भागीदार बन रहा है, लेकिन उस की समृद्धि में से राष्ट्र को जितना भाग मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है। मुझे याद है कि वित्त मंत्री जब गृह मंत्री थे, तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि हम ने सावधानी से काम नहीं लिया, तो हरी क्रान्ति, लाल क्रान्ति में बदल जायेगी। मगर इस बजट में कृषि जन्य आय पर कर लगाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

मैं नहीं जानता कि कहाँ तक ठीक है, मैं ने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि कोई महाराष्ट्र के मंत्री थे जिन्होंने शादी की दावत दी और उस शादी की दावत में सिर्फ डेढ़ लाख लोग भोजन करने के लिए आए। पड़ोसी गांव की बिजली बुझा दी गई क्यों कि विवाह के मण्डप में उजाला हो सके, क्यों कि एक घर प्रकाश के आलोक से मंडित हो सके। यह वैभव और विलास का एक भोंडा प्रदर्शन है। मुझे खेद है कि वित्त मंत्री महोदय भी वहां उपस्थित थे। मैं उन की कठिनाई जानता हूं कि जब वह वहां पहुंच गए और उन्हें पता लगा कि यहाँ डेढ़ लाख लोग मौजूद हैं तो जिन्होंने बुलाया उन को वह क्या कह सकते थे। लेकिन वह यह स्वीकार करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोगों के हाथ में जो सम्पत्ति और आमदनी इकट्ठा हो रही है उस में से राष्ट्र को हिस्सा चाहिए। साथ ही सम्पत्ति का यह भोंडा प्रदर्शन रोका जाना चाहिए। और इसीलिए हमारी मांग है......
(व्यवधान)......

एक माननीय सदस्य : ब्राह्मणों को भोजन कराया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं, यह वहाँ थे या नहीं।

हमारी तीसरी मांग है कि एक स्तर के ऊपर वह स्तर 5 हजार महीना हो सकता है, हम तो चाहेंगे कि ढाई हजार रुपये महीने हो, ढाई हजार रुपये महीने से ऊपर जो भी खर्च करेगा उसे भारी कन्जम्पशन टैक्स देना पड़ेगा। अगर वह रुपया निर्माण में लगता है, उस का स्वागत होना चाहिए। अगर वह उस से शेयर खरीदता है, कारखानों का विकास करता है तो उस पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर वह अपने उपभोग की वस्तुएं खरीदता है, अपने लिए वैभव और विलास के सामान खरीदता हैं तो उस पर भारी कर लगाया जाना चाहिए। एक तो इस से साधन प्राप्त होंगे, और दूसरी ओर सादगी का वातावरण बनेगा। लेकिन जब समाचारपत्रों में आता है कि प्रधान मंत्री के एक दिन के दौरे के लिए एक सर्किट को ठीक करने के लिए 25 हजार रुपये खर्च किए गए तो देश में सादगी का वातावरण नहीं बन सकता।

चौथा तरीका जिस पर वित्त मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार कर सकते हैं वह यह। हम ने एक ज्वाइंट सेक्टर की कल्पना की है। जो निजी कारखाने चल रहे हैं सरकार उन को कर्जा देती है, बैंक कर्जा देते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर्जा देते हैं। उस कर्जे के बदले में ईक्विटी शेयर्स प्राप्त करने का प्रयत्न हो

रहा है। इसका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन दूसरी ओर सार्वजनिक कारखाने हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सार्वजनिक कारखानों में जनता को शेयर खरीदने की छूट दे दें ? मेजारिटी शेयर नहीं, 30 प्रतिशत, 35 प्रतिशत...

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : कौन खरीदेगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोग खरीदेगें। यह भावना गलत है कि सब कारखाने घाटे में चल रहे हैं, कुछ कारखाने लाभ में चल रहे है। जो लाभ में चल रहे हैं उन में लोग शेयर खरीद सकते हैं। वहां के कर्मचारियों की शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह बन्धन लगाया जा सकता है कि कोई एक फर्म ज्यादा शेयर न खरीदे, लेकिन छोटे छोटे लोग बहुत बड़ी तादाद में शेयर खरीदें और पब्लिक सेक्टर सच्चे अर्थों में पब्लिक सेक्टर बने इसका प्रयत्न होना चाहिये। इस से कुछ साधन भी जुट सकते हैं, और अगर कर्मचारियों के, छोटे-छोटे शेयर होल्डरों के प्रतिनिधि चुन कर जाएंगे तो वह नौकरशाही पर नजर भी रख सकेंगे, उस कारखाने की क्षमता बढ़े, उत्पादन बढ़े, इस चीज में भी वह सहायक हो सकते हैं। इस पर भी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

वित्त मंत्री महोदय ने टैक्सों के कानून में थोड़ा सा संशोधन करने का प्रयत्न किया है। में समझता हूं कि टैक्सों के सारे कानून का पुनर्विचार आवश्यक है और में डा. वी के आर वी राव के सुझाव से सहमत हूं कि एक टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन नियुक्त होना चाहिए जो सारे मामलों में गहराई से जा कर विचार कर सके।

श्री यशवंत राव चव्हाण : उन्होंने एक्सपेंडीचर कमीशन की बात कही थी, टैक्सेशन की नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कमीशन उस पर भी विचार कर सकता है। और आप चाहें तो दोनों कमीशनों को एक कर दें.....

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं उस को भी नहीं मान रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप दोनों को नहीं मान रहे हैं ? मेरे सुझाव का विरोध क्यों कर रहे हैं ?

आप यह स्वीकार करेंगे कि प्रत्यक्ष कर भी इतना नहीं होना चाहिए कि जिससे बेईमानी को प्रोत्साहन मिले। अब हम लोगों ने जो हिसाब लगाया उसके अनुसार आज स्थिति यह है कि अगर एक आदमी ढाई लाख रुपये सालाना कमाता है तो उसके पास टैक्स देकर 49,325 रुपये बचेगा। लेकिन अगर वही आदमी ढाई लाख से ऊपर साढ़े सात लाख रुपये कमाता हैं तो उसके पास 16,875 रुपये बचेगा। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इन आंकड़ों की जांच करवाएं। श्री साल्वे ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। आज यह स्थिति हैं कि टैक्सों की बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। सात सौ करोड़ रुपये का इनकम टैक्स बकाया है। हर रुपये कमाने वाले को बेईमान समझा जाता है। यह वातावरण बदलने की जरूरत है। यह वातावरण बदला जा सकता है। आज जितना हम टैक्सों से रुपया वसूल करते हैं एक ओर तो उसको ठीक तरह से वसूल करने की पद्धति अपनायें और दूसरी ओर रह देखें कि क्या ऊंची से ऊंची दर में कुछ कमी करने की गुंजाइश है। मैं नहीं चाहता कि इसका निर्णय कोई राजनैतिक आधार पर किया जाये।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

एक बुर्थालिगम् कमेटी बनी थी, उसने सिफारिश की कि साढ़े सात हजार रुपये तक इनकम टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में हमने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमैंट का जितना समय, जितने साधन, जितनी शक्ति छोटी आमदनी वाले लोगों के टैक्सों की जांच करने में लगता है उतना बड़े टैक्स वालों पर नहीं लगता। नतीजा यह होता है कि बड़े टैक्स देने वाले आसानी से छूट जाते हैं और सारे साधन सारी शक्ति छोटे टैक्स देने वालों पर ही लग जाया करती है। यह सिफारिश स्वीकार की जानी चाहिए और टैक्स वसूलने की मशीनरी को ऐसा मजबूत बनाया जाना चाहिए कि जिससे बड़ी मछलियां न निकलने पाएं। आज बड़े-बड़े मगर मच्छ तो निकल जाते हैं और छोटी छोटी मछलियां फस जाती है। आज सवेरे ही एक चर्चा चल रही थी। यह जो डायरेक्ट डायलिंग है इसमें कुछ गड़बड़ी की जा रही है। किसी की लाइन किसी से जोड़ दी जाती है। काल कोई करता है और बिल का भुगतान कोई और करता है। सचार मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि हमने एक लाइन मैन को पकड़ा है और एक चौकीदार को पकड़ा है। क्या यह सारी गड़बड़ी एक लाइन मैन और चौकीदार कर सकता है? जरूर इसके ऊपर और कोई होगा। मगर मगरमच्छ तो निकल जाते हैं और छोटी मछलियां फंस जाती हैं। जाल बिछाने का यह तरीका बड़ा विचित्र है। इसको बदलने की आवश्यकता है।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए 25 करोड़ की बात की बात कही गई। वित्त मंत्री स्वीकार करेंगे कि 25 करोड़ रुपये की रकम पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए जो पहले 50 करोड़ रखा गया है वह भी नाकाफी है। होना यह चाहिए कि हम बड़े पैमाने पर शिक्षित अशिक्षित बेरोजगारों के लिए काम दें। लेकिन यहां फिर प्रश्न पैदा होगा कि साधन कहां से आएं? वित्त मंत्री कह सकते है कि मैं तो सौ करोड़ रुपये रख सकता हूं, आप मुझे साधन दीजिए।

इस सबंध में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो राज्य है इनके लिए भी कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन है या नही? हम एक नियोजित अर्थ व्यवस्था मे रह रहे हैं। हम हर एक व्यक्ति से त्याग की, बलिदान की आशा करते हैं। उज्ज्वल भविष्य के लिए वर्तमान में थोड़ा सा कष्टकर जीवन बिताना पड़ेगा इस प्रकार हमारी कामना है। लेकिन राज्य सरकारें किसी भी वित्तीय अनुशासन में रहने के लिए तैयार नही है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने अंतरिम बजट में भी यह आशा प्रकट की थी कि राज्य सरकारें जरा ओवर-ड्राफ्ट कम करेंगी और इस बजट में भी उन्होंने यही बात कही है। लेकिन क्या कोई राज्य सरकार मानने को तैयार है? स्थिति यह है कि अब सभी राज्यों के बजट घाटे के बजट हैं। राज्य सरकारें नये साधन जुटाने का साहस नहीं रखती। उन्हें आगामी विधान सभा के चुनावों की चिन्ता है। इसलिए वह सीधा रास्ता ढूंढती है रिजर्व बैंक से रुपया निकालने का। आज स्थिति यह है कि भारत विदेशों से कर्जा ले रहा है और राज्य सरकारें केन्द्र से कर्जा ले रही हैं। राज्य सरकारों के कर्जे की कोई सीमा नही है। वित्त मंत्री महोदय की अपीलें पर्याप्त नही हैं। उन्होंने स्वीकार किया है अपने बजट भाषण में कि 1970-71 में राज्यों को 195 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई मगर ओवर-ड्राफ्ट फिर भी जारी रहा। गत मार्च के अन्त तक कम से कम 14 राज्यों ने कुल मिला कर 260 करोड़ रुपये का ओवर-ड्राफ्ट लिया। अब यह रुपया किस तरह से खर्च किया जाता है, इस की भी कोई देख-रेख नहीं है। वह गैर-परियोजनाओं के व्यय पर भी खर्च किया जा

सकता है, वह ऐसे कामों पर भी खर्च किया जा सकता है जिन की आर्थिक दृष्टि से प्राथमिकता नहीं है लेकिन केन्द्रीय सरकार सलाह देने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार चाहे तो इस मामले में संविधान का उपयोग कर सकती है आर्टीकल 360 के अन्दर फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी घोषित कर सकती है। मैं उसे उद्धित करना चाहता हूं :

If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may by a Proclamation make a declaration to that effect.

15 hrs.

और आगे संविधान में कहा गया :

During the period any such Proclamation as is mentioned in clause (1) is in operation the executive authority of the Union shall extend to the giving of directions to any State to observe such canons of financial propriety as may be specified in the directions, and to the giving of such other directions as the President may deem necessary and adequate for the purpose,

अभी तक हम ने इस प्राविधान का उपयोग नहीं किया। मैं आंकडे देख रहा था कि राज्य सरकारें किस तरह से ओवर ड्राफ्ट कर रही हैं और मुझे लगा कि इस सम्बन्ध में किसी कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है। लेकिन कार्यवाही तब तक सम्भव नहीं है जब तक किहम राज्यों को डाइरेक्शन न दें और डाइरेक्शन्स आर्टीकिल 360 के अन्तर्गत दी जा सकती है। वित्त मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करें कि क्या राज्यों को इस तरह का निर्देश देने का समय आ गया है ? जब तक हम राज्यों को एक वित्तीय अनुशासन में नहीं लेगें, केन्द्रीय स्तर पर कितने ही साधन जुटाएं जो हमारा लक्ष्य है हम उस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राज्यों को इस सम्बन्ध में केन्द्र के साथ कदम मिला कर चलना होगा और यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक राज्यों को विवश नहीं किया जाएगा कि उन के पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उन का ठीक तरह से उपयोग करें।

यह ठीक है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपील की है कि साधन बढ़ाओं, नान-प्लान एक्सपेंडीचर कम करो मगर ये अपीलें कोई असर करने वाली नहीं हैं। केन्द्र को कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और एक कठोर कदम यह हो सकता है कि आर्टीकिल 360 के अन्तर्गत राज्यों को डाइरेक्शन जारी किये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश के निर्वासितों के लिए केवल 60 करोड़ रुपये की रकम रखी गई। वित्त मंत्री महोदय स्वीकार करेगें कि 60 करोड़ रुपये की रकम अयथार्थवादी, अवास्तविक और अपर्याप्त है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने में हमें 180 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेगें। इस तरह से कुल मिला कर साल भर में कितना व्यय होगा, इस का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता पर हम ज्यादा निर्भर न करें। आज सवेरे की रिपोर्ट के अनुसार शायद अधिक से अधिक 23 करोड़ रुपये की सहायता हमें प्राप्त हुई है जो ओषधियों के रूप में है, दूध के डिब्बों के रूप में है और अन्य चीज़ों के रूप रूप में है। अधिकांश बोझा हमें स्वयं उठाना पड़ेगा। 220 करोड़ रुपये का घाटा वित्त मंत्री जी ने पहले ही छोड़ दिया। इस घाटे की रकम और ज्यादा बढ़ने वाली है, निर्वासितों पर खर्च होगा और कुल मिला कर इस से मुद्रा-स्फीति बढ़ेगा, दाम बढ़ेगें, असंतोष फैलेगा और यह सरकार अपने इन नारों की स्वयं बन्दी बन जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक प्रश्न वास्तविकता का सामना किये बिना हल नहीं किया जा सकता है। आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रश्न पर भी देश में एक

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मतैक्य स्थापित करना होगा। अर्थ नीति को केवल आकर्षक बना कर हम आर्थिक नियमों को नहीं बदल सकते, नारे लगा कर हम वास्तविकता में परिवर्तन नही ला सकते। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय को अब चुनाव समाप्त हो गये हैं, सत्तारुढ़ दल भारी बहुमत में आ गया है ...

श्री पीलू मोदी : मेसिव मेन्डेट मिल गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, मैसिव मेन्डेट मिल गया है जो अब मेसिव बर्डन मे बदल गया है।

एक ऐसा मध्यम मार्ग खोजना होगा जो लोकतान्त्रिक ढांचे मे हमारे आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता के लक्ष्यो को शीघ्रता से पूरा कर सके लेकिन यह तब तक संभव नही है जब तक देश मे एक नई हवा पैदा नही की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो 60 लाख का सवाल है क्या यह नये बजट से एक नई हवा पैदा करता है। 60 लाख मे इसलिए कह रहा हू कि अमेरिका मे एक अंग्रेजी कहावत है कि जब कोई सवाल गम्भीर होता है तो उसे कहते है कि यह 64 मिलयन डालर क्वेश्चन है। हमारा देश अमेरिका नही है, यहा डालर नही रुपया चलता है। वहां डालर की बात करते हैं। हमारे यहां जब कोई महत्व पूर्ण सवाल आएगा तो उसे कहना होगा कि यह 60 लाख रुपये का सवाल है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह 60 लाख रुपये का सवाल है कि यह बजट नया वातावरण पैदा करता है या नही ?

जब 60 लाख रुपये की बात आ गई है तो मैं यह कह कर खत्म कर दू कि वित्त मंत्री महोदय जब जवाब दें तो यह भी बताएं कि स्टेट बैंक से जो 60 लाख रुपया निकाला गया वह किस मद में से निकाला गया ? इस प्रश्न पर अभी तक प्रकाश नहीं डाला गया है। यह प्रश्न अदालत के विचाराधीन भी नहीं है। नागरवाला महोदय ने 60 लाख रुपया निकाला, मल्होतरा महोदय ने 60 लाख रुपया दिया, वह स्टेट बैंक के किस मद मे से निकाला गया यह सदन जानना चाहता है, यह देश जानना चाहता है और मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय, इस पर लीपापोती नही करेंगे और तथ्यो को सदन के सामने रखेंगे।

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA (Cachar) : Sir, in moving to support the Budget proposals, I deem it my duty to bring certain points to the notice of the Government.

I presonally represent a constituency which suffers from lack of transport facilities, unemployment and economic distress. The geographical position is such that the three sides are covered by hill areas and one side borders Bangla Desh.

The tragic happenings in Bangla Desh have resulted in the exodus of evacuees from there for the last two months, Now the Pak army is entering into our territory and killing our people. Our border security forces deployed for this purpose are not sufficiently capable to combat with the Pak army. Army should be employed in border areas for security of our people.

I have no need to mention about the atrocities being done by Pak army in Bangla Desh which has been discussed in this august House, but two things I have got to mention clearly. First, for about a month, now the Pak army have made it a point to drive out the minorities from Bangla Desh. Secondly, atrocities on women have gone beyond the concept of civilization.

The entire world is keeping thier mouth shut ; the conflicting major nations are apparently one in silence. Should we in India

bear all the brunt of Pakistan's misdoings ? Can we not ask the nations who have economic interest in our country to come out in condemnation of Pakistan and suspend all financial assistance until and unless Pakistan restores peace in Bangla Desh and takes back the evacuees by creating a peaceful solution there ?

For the last 23 years, Pakistan is always trying to create direct and indirect pressure on India and we have to suffer each time.

It is high time that Pakistan should be asked to hand over territory proportionate for settlement of evacuees forced out from time to time. The demand must be backed by the might of our armed strength.

Now, I come to the Communication question. For us, the Railway track is the main link. As we are faced today, my request to the Government is that the hill section portion from Lumding to Badarpur in N.F. Railway must be given special attention. Night-running of trains in this area should be restored immediately. The other day, the Chief Minister of Nagaland had stated that the Naga problem had been tackled properly ; if so, there should be no difficulty in introducing night-running of trains, will lessen overcrowding.

I would like to mention that unemployment and economic distress can be mitigated to some extent if the proposed paper and pulp mill and sugar mill projects are implemented immediately in this area. The Mizo Hills district is rich in mineral resources, which can be tapped by the Government. Fruits like oranges and pineapples are in abundance in this area, and so, a fruit preservation factory can easily be established here.

The proposed Barak dam project will help agricultural proposes and would also provide cheap power. I would humbly request the Central Government to expedite this in consultation with the Manipur Government.

I would like to draw the attention of the Government and the House to the position regarding education in my district of Cachar. It is a Bengali-speaking area, and it is under the Gauhati University where there is no recognition of Bengali at the university level. A medical college had been set up in Cachar only three years back, though it was expected to be established there during the Second Plan period. Even now, it is not properely looked after ; there is neither proper or required teaching staff who have been appointed, nor has a properly equipped hospital been provided during these three years, nor have suitable buildings been completed. The construction work has been entrusted to a Government-sponsored body which does not care to a accelerate the speed of the construction work. The students of this college will have to appear examinations in subjects for which they have not been coached here due to shortage of teaching staff.

A regional engineering college was expected to function here for the last three years, but I understand that before any construction has been undertaken, a principal and some teachers have been appointed, who stay outside Cachar. Is it not a colossal wastage of money ?

I would request the Government to investigate into these matters and take proper steps to start teaching in the engineering college and also equip the Silchar Medical College to attain the proper standard so that the graduate of this college will get proper acceptance by the Indian Medical Council, and also to get Bengali accepted as one of the languages along with English and Assamese at the university level.

Before I conclude, I would request the hon. Finance Minister to consider his proposals to levy taxes on maida, coarse and medium cotton textiles and ready-made garments. All these items are used by the poor and middle class people of our society. The exise duty levied on petroleum will definitely result in rise in transport costs which will again hit the poor and middle class people.

We have taken the vow *Garibi Hatao*. Does the hon. Minister think that by the levy of such taxes, poverty will be driven out ? Is it not the case that the poor and middle class people will be compelled to

[Shrimati Jyotsna Chanda]

become more and more poor ? So, I would humbly request the hon. Minister to withdraw such taxes and give more attention to tightening up measures to stop tax evasion, so that the defict could be met.

With these words, I support the budget.

SHRI B. R. BHAGAT (Shahabad) : The hon. Finance Minister has done his best of an almost impossible task that faced him. It is natural that the Members of the Opposition should attack him by picking out certain shortcomings in the budget proposals as they see it.

Sir, I would submit that the budget is like a modern art picture or a modern art gallery, where those who go to see it like to see the picture as they want it and criticise it because it does not turn out to be according to their expectation. That is the reason why I find that there is a curious similarity in the line of attack on the budget adopted by Shri Atal Bihari Vajpayee on the one side and Shri Indrajit Gupta on the other, or for that matter by the other leading lights of the Opposition. Each one of them tried to see it as he wanted to through his own eyes.

For example, Shri Indrajit Gupta who criticised the budget thought that the Finance Minister would present it in an ideological pattern would build up a socialist society as he wanted it to be built up, and since the budget does not fit in with his pattern, naturally he attacked the budget. Similarly, Shri Atal Bihari Vajpayee has still not forgotten that the Congress Party has got a massive mandate, and, therefore, he tried to confuse the picture by saying that it had been converted into a massive burden or a massive or rising discontent in the country. There are all the imaginary illusions that he has tried to create.

The fact of the matter is that here is a budget presented in the background and in the light of the most difficult economic situation in the country. The situation is most difficult not because of the fact that there is a complexity created by any policies but because of the fact that ours is a big society consisting of 550 million people, a society torn by various pulls and divisions, and which is at the bottom of the economic level. There are also practical difficulties in working within a democratic framework with full freedom for all so that each section of our nation gets proper representation in the Government and Parliament. It is in this background that we are trying to change the social structure of the society in a democratic way. That is the difficulty that we are facing. So far as Shri Indrajit Gupta is concerned, it is quite easy for him to accomplish this task, because he has no public opinion to look to. He can straight-jacket society and bring about the change. But we have to look to the people, and, therefore, we have to interpret their mandate as they have given it, and we have to interpret it as we see it in the light of our commitments to the people. But that is not the way that others interpret it. Therefore, Shri Atal Bihari Vajpayee may find that it is not a massive mandate but it is a massive burden.

But, in fact, what is the actual burden ? Take the taxation proposals ? I do not think that any Member of the Opposition will find fault with the big effort that the Finance Minister has made in raising resources. In one single year, he has sought to raise the largest amount of resources. I do not think that this position is challenged by any Member. Actually, hon. Members would like that in view of the commitments that we have made to the country, whether it be the commitment for development, or the commitment for accelerating the rate of growth or the commitment to the unfortunate refugees from Bangla Desh who have become in an unpreeedented number, or the various other commitments, the Plan outlay has to be stepped up. Yesterday, Dr. V K.R.V. Rao said that we had to step up the Plan outlay. I think Shri Indrajit Gupta also would like it to be stepped up. I think even Shri Atal Bihari Vajpayee would like the Finance Minister to find all the resources possible so that he does not leave a gap of Rs. 220 crores because otherwise it would add to the burden on the people. But when he actually tried to raise resources to the tune of Rs. 177 crores, Members find fault with him. In my opinion, he could have done more, but then there is a limit in a democracy. He has to weight the various forces in the

country. So, when any Member finds fault with him that he has imposed a massive burden, the two things do not go together.

I do not want to go into the details, but if you look into the pattern of taxes, you will find that he has done an excellent job. A peasant that he is, he has seen to it that the burden does not fall on the poor people. With his sturdy commonsense, he has said that the philosophy behind his tax proposals could be summed up in three main principles. He wants to rationalise the tax structure. If anybody wants to do it at one stroke, it cannot be done. But he has tried it. Then he wants to distribute the burden to the more affluent sections of society ; he never claimed that there will not be a single burden on the middle class or the common people. There cannot be any scheme of taxation where the common people will not have to bear any burden. If the burden is very equitably distributed, if the common people also are to bear the minimum share of the burden and if the affluent sections are going to pay more, I do not think there can be any legitimate ground for criticism. Thirdly, he has said that he is trying to distribute the tax burden so as not to add to the inflationary spiral. He has squarely faced the issues and placed them before us. Judged from these points of view, the tax proposals come before us in proper perspective.

Take the wealth tax. For decades there have been yearnings in this House that there must be ceiling on wealth, there should be no windfall wealth in a society like this. By his wealth tax proposals, he has almost tried to achieve a ceiling. He could not do it by law, but he has done it through the instrumentality of taxation of wealth. Now if anybody has more than Rs. 8 lakhs, he will find it not worth it ; it will be going out of his net assests.

Then take the income tax. I do not think his proposal to increase the rate of surcharge on incomes above Rs. 15,000 can be criticised strongly because we have to see that the burden is distributed as equitable as possible.

I will come to the price aspect later, as it is a very significant factor in our econonmy ; we cannot analyse it only in the light of the tax proposals. I would only say that this stage that the taxes as they are, whether the wealth tax or income-tax or the tax on the corporate sector through the capital gains tax or the removal of the development rebate, are not by themselves going to affect the price spiral. I am basing this on facts.

He has rationalised the tax structure so far as import duties are concerned I wish he goes further in that direction. Instead of four slabs, there should be two. He has made a beginning. From all these points of view, he has done an excellent job and it should be commended.

Now I come to the objectives of the budget. The budget is an important instrument of economic change. It is an integrated process over the years ; we cannot achieve all our objectives in one budget ; economic change, social change and growth have to be brought about by a series of budgets. Let us examine the budget from the point of view of these objectives. The President in his Address says that removal of poverty is the main objective of this Government. This is the mandate the people have given us. Before I go into details, I can say without fear of contradiction that no person here or no sensible person outside believes that poverty can be removed overnight. We have to make a big effort for years together to conquer poverty and usher in an affluent society where everybody gets social and economic justice. But the direction is important. Are we going in the correct direction or not ? I venture to say this budget has given the correct direction and if we follow along this line, sooner than later we will be able to tackle the biggest problem the country faces, the problem of poverty.

In economic terms, how do we analyse this problem. There are four aspects to to it ; that problem of unemployment, the problem of level of prices, price stability, then social justice, how the wealth is being distributed, and of growth. All these are inter-related. There cannot be any employment without higher rate of growth. There cannot be growth without price

[Shri B. R. Bhagat]

stability. With runaway prices, there cannot be social justice ; under inflationary conditions, the income of the poorer section will move towards the richer section. Now I would like to offer some suggestions for his future guidance, which I hope he will consider.

First take growth. Yesterday, my colleague, Dr. Rao, analysed it, His conclusion—it is a right conclusion shared by other members—is that the 5.5 per cent growth is not enough to give employment to everybody in the foreseeable future. I am glad the Planning Minister is having a reappraisal of the Plan. Let him come forward with a scheme of orientation of policies and programmes and priorities providing for a higher rate of growth. I think this is possible. I must compliment the Finance Minister on the lucidity of the Economic Survey. He has honestly and straightforwardly analysed the price situation. If anyone reads through the 2½ pages he has highlighted the tasks ahead. From this it is clear that we have to go in for a higher rate of growth than merely 5.5 per cent. In the last two years, we had this growth but the Finance Minister has put this in a pregnant line that "the economy is poised for a bigger task". The social and economic infra-structure is there ; the administrative structure is there ; the will of the people is there ; the mandate is the will of the people. If there is a strong will in Government and in this House, I think we can attain a rate of 8-9 per cent growth. It is the only answer to the many problems, including the problem of prices, we are facing. He has pointed out that he could only provide additionally Rs. 155 crores for the Plan ; although the last plan did not achieve its full quantum, the additional increase is of the order of Rs. 3000 crores. I wish it could have been more. I know there is a limit to the physical means of raising resources. But there are other ways. I wish the Finance Minister would consider other ways in which resources can be raised and the urgent task of augmenting plan development finance met. Once the priorities are settled, finance can be found. If we want to meet our stated commitment of providing one person in every family with livelihood of at least Rs. 100 per month, it means providing 120 million jobs for 120 families. Granting that some are employed, you have to provide at least sixty million jobs. This cannot be done at the present rate of growth. That is the size of the problem. The budget can be a massive burden only when the objectives with which it has been framed are not realised, if the growth rate is not realised, if employment does not increase and if price stability is not achieved and if social justice is not cared for ; only then it becomes burden, otherwise not.

Take the question of price stability. We have the nationalised banking system. The unfortunate tendency for the money supply has been to increase at a faster rate ; it has been unregulated. There is a close link between the money supply, annual growth rate and the price increase. If you know the money supply and the growth rate you can predict what will be the price rise this year or the next year. In 1965-66 the money supply increased by 11 per cent but the net national product declined—it was a bad year—by 15 per cent and the wholesale price index rose by 13.6 per cent. In 1966-67 the money supply increased by 9.3 per cent and the net national product increased by 1.5 per cent and inevitably the wholesale price index rose by 11 per cent while in 1967-68 the money supply increased by 8 1 per cent and the net national product increased by 9.3 per cent and the wholesale price index went down by 1.2 per cent. In 1970-71 money supply increased by 12.1 per cent though we have a nationalised banking structure, it is the highest ever increase, and the net national product increased by 5.3 per cent—that is our plan target and we have achieved it in the last two years—and the rise in price was 5 6 per cent. Therefore I am saying that we must achieve a higher rate of growth if we want price stability.

There are structural imbalances. Food crops have been good and their prices have come down but other prices have gone up. The general level of prices have gone up. It is not enough to have overall growth. Nutritional imbalances are created because pulses are not grown. There should be balanced growth in the industrial sector, in food crops, cash crops and also pulses. Growing wheat is perhaps more profitable

and so the production of pulses is going down which affects the nutritional balance. All this is creating problems and the Finance Minister and the Planning Minister should look into this and see that not only the general rate of growth goes up but that the other factors also are looked after.

How are we to achieve this growth ? I have two suggestions to make. The Finance Minister has done an excellent job within his limitations of providing tax proposals and fiscal measures. There are other measures by which we can raise resources. I had suggested earlier that the import duties should be raised to 50 per cent level ; he has done it in the budget by introducing four slabs 30, 40, 60 and 100 per cent. There is a fifty per cent appreciation in foreign exchange ; anybody who gets an imported machinery has its value appreciated if he uses it well. The unit cost must go down ; the Finance Minister has said so very rightly. For exports, for achieving higher productivity, etc. unit cost must go down. If a person imports machinery and raw material even by paying 50 per cent import duty, he will be able to produce goods at a lower unit cost provided he uses it at the maximum level. That can give him Rs. 200 or Rs 300 crores additionally.

Secondly, I refer to the interest rate. We are used to the old way of the British commercial banks. The Reserve Bank is the biggest culprit in this matter ; they will look to their gilt edged securities and say : what will happen to Government loans, they are doomed. Therefore, there should be no rise in the interest rates ; that is what they will say. But what is the situation in Japan, Yugoslavia and Germany ? Their rate of growth is 15 per cent ; the rate of interest is 13 per cent ; they have also a high rate of employment. We have followed the reverse practice 5.5 per cent or 6 per cent rate of interest. There is negligible employment and the rate of growth is 5.5 per cent. Everybody says that an affluent sector is developing in the rural side creating socio-economic and political problems. Cannot we offer them higher rate of interest and float special unemployment debentures and give them 12 per cent. When the rate is 6 per cent today, who will invest money from the rural sector ? Give them 10 or 12 per cent and you can raise Rs. 300 or 400 crores in one year from the rural sector. If you make special allowance they can give you more money upto Rs. 500 or 600 crores and you can invest it in the Plan and achieve higher rate of growth and create more employment opportunities. Then alone all the four objectives of higher growth, fuller employment, price stability and social justice will be achieved and if our friend Mr. Vajpayee says that this budget is a massive burden people will give a lie to him. I want these objectives to be realised. With these words I support the budget.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am quite conscious that I am joining the fray when the excitement is almost over. But I must say right at the beginning that I welcome this budget for being a very good gift to the Opposition. I did not know that the Finance Minister was that kind to the Opposition. But as it has turned out to be it is a good gift and I would not exclude from the list of beneficiaries even the DMK or the CPI who seem to have a clandestine love affair with the ruling party.

I welcome this as being the best confirmation of the worst fears and warnings that we had conveyed to the people about the actions and the deeds of the ruling party. I also welcome it as the best refutation of what the ruling party had said to the electorate during the elections by way of mass bribery.

The Government will have to thank for themselves if they now find that they have been forced to the brink of almost complete disillusionment of the people. It is not the opposition which had pushed them to this brink ; it is by their own act of volition. It seems to me that the three B's, that is, Bangla Desh, Bank Cheating Case and this Budget will have almost brought the credibility of the Government to zero. I am not saying this to satisfy myself. I know the reply that would be coming from the hon. Finance Minister later (*Interruptions*). If they have any doubt about the credibility of the Government having touched the nadir, may I ask them to take an opinion poll right in this city of Delhi. I would venture to say that not even one per cent of the total population of four million or so of Delhi, only the 350 sitting right in front of me and that also under duress and under the party whip, would be voting for you. So,

[Shri Shyamanandan Mishra]

it appears to me that only 0.001 per cent of the population in Delhi, at this point of time, would support this budget.

Now, Mr. Deputy-Speaker, let me comfort the minds of my hon. friends on the other side: it is one of my sadnesses that it should be so, because although we have split into two, the bonds of fraternity have not snapped completely. So I say that this is one of my sadnesses. We would certainly like to support the Government warmly and whole heartedly in this hour of grave crisis. Indeed, there is nothing less than a crisis which is confronting the country at the present moment, and if the Government does not reflect it, I must say that the events will push it out of the warm bath of complacency in no time.

It is, therefore, quite clear in my mind that this cyclone which seems to have hit the country earlier is going to change its direction, and its velocity might remain the same. To repeat, the velocity and the virulence of it might remain, but the cyclone is going to change the direction.

Now, therefore, if this phase develops in the country, would we be happy about this, from the larger national point of view? I have no doubt, as I said, that the crash in some form or the other might come. No one had predicted when Mrs. Bandaranaike became the Prime Minister of Ceylon that there would be a crash in store for Ceylon, a crash the sound of which could be heard on the Mars. But it did happen in Ceylon, and if that happens here too, would we turn round and say to the Government, we told you so? Would we comfort ourselves by saying so? Let me assure this hon. House that to that the answer would be an over whelming no, fo far as we are concerned. And we would certainly try to do everything in our power to see that such a situation did not develop. We do not want to allow the architects of disorder to have full play in the country so that there is a situation like the one in the Ceylon or even like a situation that developed in Indonesia earlier.

Now, I do admit that the hon. Finance Minister had an extremely difficult task to perform. But the question that I want to ask is : could he not courageously and realistically face up to this task? My humble submission is that he has not faced up to this task realistically or even courageously. This is a most unreal exercise in budget-making that I have come across during my 21 years of Parliamentary life. It is an attempt to look normal when the circumstances are really abnormal. Abnormality has been introduced by two or three factors. One is the new-style Pak aggression over this country and *vis a vis* this the warm bath complacency exhibited by the Government. Secondly, the abnormality is also introduced by holding out hopes of instant socialism by the ruling party and soon after retracting from it.

The question, therefore, that arises is whether it is a budget at all, and could there be a budget in the given circumstances which might have even a modicum of economic sense or rationality? My main submission is that so long as this Pak crisis continues and we continue to remain a victim of Pak aggression, there can be no rational budget worth the name. This is what the Finance Minister has tried to glossover. At least this much he could have done, namely, he could have posed challenges to the country and brought out all the dimensions of the economic problem with which we are faced. But he has tried to conceal the many dimensions of this problem and therefore we find that this is a budget which cannot be considered to be a credible budget at all—or a rational budget for that matter.

Take, for example, this puerile estimate for the refugees—of Rs. 60 crores for the evacuees from Bangla Desh. The most modest estimate would be at least Rs. 2 crores to Rs. 3 crores per day and during the course of a year it is bound to be of the order of Rs. 720 crores of Rs. 800 crores. That means it would absorb almost the entire resources that are available for the defence budget and almost three or four times the expenditure that we incurred on the Indo-Pak war in 1965. We ask you whether we can reconcile ourselves to this estimate of Rs. 60 crores and then endorse the rationale behind this budget. That simply cannot be done.

Therefore, I say this is a very irrational attempt ; it is an attempt which does not even ask the country to be stir itself. The country could have certainly done that. What I have found during the course of the last few years is that although such an opportunity presents itself, we generally muff it. And this was a great opportunity indeed, to arouse the country to come forward and rally under the banner of the Government with the required amount of resources and sacrifice. But also the governmeut has not done. This also shows that this is not a real bodget.

We have been told often times that there is going to be a reappraisal of the Fourth Plan—almost a reformulation of the Fourth Plan. Although it holds out some hopes to the people, I must say that there is a pseudo-radical approach to the whole problem of planning. When our planning has got back to the rails, an attempt is again being made to throw it off the rails. So many things are being held out by way of sop to the people, but planning cannot afford such pseudo-radical gimmicks. However, if there is a hope that the Fourth Plan can be reformulated to the great benefit of the masses, we would certainly co-operate with this exercise. But let it be borne in mind that if it is going to be so, then this is not going to be the real budget ; the budget will have to be revamped and reformulated too. Therefore, I do not consider it for that matter also a real one.

It is my submission, that we had got earlier this year an interim budget, now we have got this unreal budget, then there would come the real budget, which would again be followed up by a supplementary budget. A wonderful series of budgets we are going to have during the course of this year.

SHRI PILOO MODY : Then a bankrupt session.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Much is being said about the eradication of poverty, socialism and massive mandate. Now may I submit that whenever some of us sitting on these benches feel any dullness we pray to God that two phrases might drop from some lips to relieve our dullness. And what are those two phrases ? They are "massive mandate" and *"garibi hatao."* The moment those words are used we seem to be bursting with laughter and all our dullness goes. That has been happening for the last few days we have been sitting here.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : Is is because of the humilation you have suffered in the mid-term elections ?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : You can have all the pleasure and all the euphoria, although your euphria is proving to be shortlived now.

No one had expected that this would be an anti-poverty budget although the person who served the notice of "quit poverty" has now joined the Central Cabinet to strengthen the hands of the hon Finance Minister. I hope he remembers the great person who had served the notice "quit poverty". It was Shri C Subramaniam, now the celebrated Deputy Chairman of the Planning Commission and the Minister of Planning of the Government of India. It was he who, after the split, during the Bombay session of the Requisitionists' Congress, said : It is this Bombay which had served the notice of 'quit India' and it is this Bombay which is again serving the notice of "quit poverty". If this were the intention of the Government, namely, to serve the notice of "quit poverty" one would turn round and ask why did the Prime Minister say to the Rajya Sabha on the 19th November 1970 that the basic minimum needs of the people could not be fulfilled by 1975-76. It is in the records of Parliament that the Prime Minister had said that the basic minimum needs of the people could not be fulfilled by 1975-76. And, mind you, this was a commitment given by the United Congress to the people of India at the Bhubaneswar session of the Congress in 1964. It was repeated in the Election Manifesto of 1967 and against repeated in the famous Ten-Point Programme. It is this very cardinal objective of the Ten-Point Programme which has been quietly shoved away by the hon. Prime Minister and the Goverament of India They have now thrown up their hands saying that this cannot be done. So, I ask you, who is fulfilling the Ten Point Programme ? Who is abiding by the Ten-Point Programme ? Was this not the most important item of the Ten Point Programme? were not the othor programmes peripheral and marginal in nature, only subsidiary to this main point, that is, the

[Shri Shyam Nadan Mishra]

fulfilment of the basic necessities of life of the people by 1975-76? And yet we are being asked to believe them when they say that they are really serious about the eradication of poverty!

Again, I would like to remind hon. Members that soon after the elections the Prime Minister was honest enough to say that what she said about the eradication of poverty was nothing extraordinary, and that she had no magic wand to eradicate poverty overnight. When a German journalist asked her : "your father also promised the eradication of poverty, can you give any time-limit ?" she said "there can be no time-limit for this". Now, that being so, you can imagine who would have expected that this budget could be a budget for the eradication of poverty.

Moreover, poverty cannot be attacked with a poverty of ideas. For attacking poverty you have to have ideas, the understanding of the extent and death of this problem and the perspective in which this problem could be solved. This cannot be done by augmenting the heat-waves of your words or by indulging in populist demagogy. This cannot be done in that way. Even the Conservatives, let this hon. House remind itself, when they came to power last time they had also raised something like the slogan of "eradication of poverty" and probably Shrimati Bandarnayake had promised something more. Thus a claim could not be made on behalf of this budget that its main ethos is the eradication of poverty. If that by any means the claim, then here are some tell-tale evidences that all its basic postulates are quite diametrically opposed to this.

Let me mention a few postulates of the budget, as I understand it. One is,—and this is no falsification of the main theme or the main postulate of the budget attempted by a person who belongs to a party which would like the other party to go down ; at any rate that is not my intention—as I see it, the main thesis of this budget is that poor will have to become poorer in order to be poverty-free in the long run. I think I am clear on this point that they will have to become poorer, has been established by everybody on this side. It can be established by them too unless they are living in some kind of make-believe world, in the world of self-deception, that the poorman's rupee is going to be eroded and their standard of living is going to be brought down. So, that it one of the main these of this budget. Naturally a carollary of this will be that the rich will have to be tolerated or permitted to become richer in ordered to yield resources for the uplift of the poor. Therefore, you would find that the corporate sector has been let off completely. And this is not the first year when has been done. It has been done in a row for the last three years or so, as I recollect it. So, this is another postulate that we have. Then we find that there is no perspective, no time horizon that it held out by this budget in which one could hope that this enormous problem could be solved.

Therefore, one is bound to ask : if this is the charter for the common man, what could be the charter for the rich ?

16 hrs.

So I am constrained to say that this Budget does not meet the needs of the common man at all. In fact, the real test of any budget should be as to how it serves the common man in terms of employment, increased income and setting trends for the achievement of good life which the Third Five-Year Plan had placed before to the people as goal. May I remind this hon. House that this objective of the achievement of good life was placed before the country by no less a person than Pandit Jawaharlal Nehru ? So, the common man would try to find out from the Budget whether trends are set in that direction. We do not find anything of that kind in it.

The ruling party does not even benefit from the advice of some important persons whom it invites from foreign countries to deliver lectures to us on important subjects for our advantage. Only a few months back the great Nobel laureate, Professor Tinbergen, had come to deliver the Jawaharlal Nehru Memorial Lecture. He gave a talk on "Mature Socialism". What did he have to say about Mature Socialism ? He said that mature socialism means institutionalisation of solidarity in the society and the recognition of the fact that the community was ultimately responsible for the welfare of the individual.

But his main test was the maximisation of the human welfare function. Whether it brings about the maximisation of human welfare function, should be the real test in judging this Budgets, and must say that it is stunning disappointment from that point of view too.

But how did one get the hope that this party would be able to deliver the good so far as the eradication of poverty is concerned. The problem which could not be solved during Pandit Jawaharlal Nehru's time would be solved during Shri Chavan's regive or for that matter during Shrimati Indira Gandhi's regive ? Do they have a much better political organisation with a great sense of dedication and commitment to the cause than they had in the past ? If that is so, we would all be happy for it. Have we got a much better admininistrative set-up, more cooperative and more efficient, to undertake the task ? If not then, what does socialism consist of in reality ? Does it consist of words or does socialism require something more than a generous use of words ? Therefore I would submit that this Budget does not all take us in the direction about which very loud claims have been made by some hon. Members.

Now let me come to the topic of socialism. I have been telling my friends—and I think it would bear repetition here—that in spite of all the frills and fripperies of socialism that have been sought to be given to this Budget, it does appear to me that the anti-people nature or the anti-socialist nature of the Budget remain in hot pants. It is very clear. What the anatomy of this Budget is, it is not very difficult to find out. With all the Victorian folds of garments that the hon. Minister has tried to give to the Budget its basic nature remains in hot pants.

Why do I say so ? Only about two or three weeks back, or maybe one or two months back the hon. Defence Minister of the Government of India was pleased to say that not even in the next half a century India could think of attaining socialism. The Prime Minister, soon after the elections, was pleased to address the Federation of the Indian Chambers of commerce and reassured the industrialists and businessmen "Who has told you that we are your enemies ? We are your friends," We do not want the Prime Minister to be the enemy of the industrialists or the capitalists, but the fact that she did think it necessary to reassure that audience, means that she was not going to make any effective attack on them. How are you going to solve the problem of poverty without attacking property ? The main issue in a democracy is whether poverty would use democracy to attack property or whether property in fear of poverty would destroy democracy. That was what Aneurin Bevan had asked at one time an important figure on the British socialist scene.

I do realise—and I would whole heartedly agree with the Finance Minister—that a budget is only of a marginal or peripheral significance so far as the shaping of the contours of society is concerned. There are other more important thinks to be taken care of and the most decisive determinants are the social and economic policies of the Government, the strategy of social transformation and the character of the ruling and administrative elite which is charged with the responsibility of carrying out these policies. These are broadly three basic determinants of the nature of a society.

Now let us examine this Budget. I must say that the raw head and the bloody bones of this Budget would be found in the cupboards of the social and economic policies of the Government of India. And what were the policies recently promulgated by the Government of India. In spite of them the Government seems to be strutting about the stage as if it is going ahead with the programmes of social and economic advance !

The Government of India, as I told you a moment ago, has already given up its goal of meeting the basic requirements of the people by 1975-76 Secondly, what is more important that has happened—and they have gone away, it seems, with perfect impunity—is that they have brought down the main instrument of socialist advance, that is, the Planning Commission, in prestige, weight and influence. The Planning Commission has been emasculated and rendered almost redundant and vacuous by the Presidential notification. It has transfered all the functions of Planning Commission to the Ministry of Planning.

[Shri Shyamnandan Mishra]

Now we are being told that there is going to be a change in the personnel of the Planning Commission. Some change has already occured. But may I say that the stature of the Planning Commission seems to be going down every day and whatever chess you might play with personalities, you cannot bring about the real chahge that you want to in the Planning Commission only by these methods ?

Thirdly, the House must take note that the Government has promulgated a policy which now opens out the doors of the core industries to the big business houses. What do we exactly mean now by commanding heights of the economy being in the public sector ? I really do not understand that. If the "core" goes to the private sector, then what remains with the public sector ? So, I frankly do not understand all this.

It has also been pointed out by some other hon. Members that everything possible has been done by this Government to stifle the Monopolies Commission so that it is like the policeman looking the other way. It does not look at things which are happening merrily in good old ways. Therefore, much hope that was being pinned on this Monopolies Commission comes down to ashes.

Recently, there was a glaring deviation from the industrial policy also in sanctioning what are called the mini-steel plants. There are going to be six of them and each of them of the order of only 50,000 tonnes at the present moment. But who knows economics of scale would not weigh on them later and it will go upto any length and upto any amount. These mini-plants were given by China quite a few years ago. The cost of production of Indian steel is bound to go up. It is these marginal units which are going to raise the cost of steel in this country.

Then, quite understandly, we have now the policy of decontrol in sugar and earlier, quite some time back, there was decontrol in paper. This Government like an honest debtor had to do something for their creditor. Industralists and businessmen must make money after they had been able to help them a bit during the most crucial period of their existence. So, now decontrol has been promulgated in sugar and earlier decontrol was promulgated in paper.

I have told you that it is the character of the ruling elite, administrative elite which determines the nature of society. What this elite has been doing is plainly this : it has been radiating irrationality. It does appear to me that economic rationality is the greatest casualty at the present moment. If the towers of power radiate irrationality, there is hardly any nooks and corner in the country which can remain immune from it.

Then one of the most crucial tests of social advance is the ratio between public and private investment. How has this ratio been behaving ? Let us examine it on the basis of developments that have been taaking place during the first two years of the current Plan.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please try to conclude now.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : I have yet to speak on the taxation proposals of the Budget.

It is clear from the development in the first two years of the Fourth Plan that the earlier trends has been completely reversed. The socialist vehicle seems to be running in the reverse gear. Let us have a look at the relevant figures of 1969-70 and 1970-71. In 1969-70, the ratio between public and private investment was 53.2 and 46.3. In 1970-71, it was 51:49, that is, running close to 50:70. This year, the position may be worse. What happend during the Second Plan ? The ratio was 54.1 and 45.3. In the Third Plan, it was 60.6 and 39.4. So, this ratio is becoming adverse and we find that the investment in public sector is going down. What is the hope then for socialist advance I do not know.

The real test of the Budget should be in terms of the Plan and progress. What has happend, so far as two years of the current Plan are concerned, in

respect of the achievement of the target of increase in national income ? Much has been made of the fact that we have had an increase of 5.5 per cent in national income during last year. May I have the audacity to challenge it. I have my doubts whether there has been really an increase of the order of 5 5 per cent in national income during last year ? It requires a little elucidation. If in the year 1969-70 there could be an increase of the order of 5.3 per cent in national income on the basis of 6.5 per cent increase in agriculture.....

MR. DEPUTY SPEAKER : Please conclude now.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Yes ; you allow me a few minutes more. If on the basis of 6 5 per cent increase in agriculture, it was a little over 3 per cent, how does this come about ? This time, there has been only a little over 5 per cent increase in agriculture. How could it be 5.5 per cent increase in national income lost if it was only 5 3 per cent on the basis of the figure that I have given.

There is another doubt about this. The Plan stipulation was that there will be 5 per cent increase in national income on the basis of 8-10 per cent increase in industrial production and 5 per cent increase in agricultural production. A a miracle has happened that on the basis of 5 per cent increase in both agriculture and industry 5.5 per cent increase in national income has taken place.

Further, much could not be made out of this. Because this is based on stagnation, more or less in industry. It is based mostly on agricultural production. Therefore, the whole process of economic development seems to have received a kind of set back during the course of last one year or so.

MR. DEPUTY SPEAKER : You have taken more time than what is due.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Just 2 minutes more.

Coming to taxation proposals, no one expects the Finance Minister to produce socialism fiscally. There is nothing like fiscal socialism or fiat socialism or legislative socialism. The principles adumberated are indeed unexceptionable. My submission is that he has acted against the principles which he has enunciated in the Budget itself, Firstly, he has acted against his principle of holding the price line. He has done everything possible that will increase the price line. Then he has left the deficit uncovered to the extent of Rs. 220 crores. Then, he has imposed inflationary taxation. Even this deficit of Rs 220 crores one cannot believe. He has claimed that he will be imposing burdens only on luxury and semi-luxury items. But what we find is that hardly any item of necessaryit has been left out, even the bread is not an exception. That reminds us of what was said by a Nazi agitator : "we don't want lower bread prices, we don't want highest bread prices, we don't want unchanged bread prices, we want national socialist bread prices." Now, it seems it is the Chavan bread prices that they want. Therefore, Government thinks that people will be able to put up with this kind of thing. Even if you examine it from the point of view of the balance between the direct and the indirect taxation, you will find that it is regressive. This is ironic that this has been so this year.

MR. DEPUTY SPEAKER : That is all now.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : I am sorry I have not been able to cover many of my points. I thought that I would be getting 40 minute.....

MR. DEPUTY SPEAKER : You have had more than that.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Thank you very much. With these words, I have done.

SHRI M. SUDARSANAM (Narasaraopet) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, I would unhesitatingly say that this year's Budget reflects the urges and aspirations of the common man to a great extent.

This Budget spells out a philosophy of emoval of glaring inequalities in wealth rhrough increase in taxation above the tassessable value of Rs. 40,000 by placing

[Shri M. Sudarsanam]

additional burden of wealth tax and additional wealth tax on urban lands and buildings. If one makes detailed calculations, one will realise that above a certain value of property and income, the net amount payable by way of income-tax and wealth-tax would be over 100 per cent.

16.20 hrs.

[SHRI N. K. P. *Salve in the Chair*]

The Budget should have exempted corporate profits of above 25 per cent provided they are ploughed back into industry resulting in increase of job potential and gross national income.

Further, I would like to suggest that to encourage savings, those that come into the orbit of wealth tax should get certain exepmtions provided they make investments upto Rs. 1 lakh additionally in Government securities. This would be a direct form of saving.

To combat the poverty and solve unemployment problem, we must do some hard thinking on further improving agricultural, industrial and mineral production. Unfortunately, the impact of the Green Revolution has not percolated to the cash crops. The transfer of improved technology can reach desirable proportions only if it covers cotton, jute, oil-seeds and other types of agricultural products,—including tobacco. Increase in mineral production through appropriate incentives can result in greater employment.

It is very unfortunate that the Budget is not export-oriented. Coming as I do from an area which has a lot of export consciousness, because tobacco is an important foreign exchange earner, I cannot but keep referring to the inadequacy of the measures taken for promoting exports. We were assured on several occasions, about the formation of the Tobacco Board. But this is being delayed for one reason or the other, since a long time. In view of the tremendous global competition, Indian tobacco cannot realy stand in competition with other growing countries, in view of the levy of export duty. This export duty must be abolished in the interest of foreign exchange earnings.

Sir, I suggest that we should endeavour to increase employment and employment opportunities in productive effort and not through increase in administrative expenses. The public sector units should function efficiently and economically when alone our economy can improve.

I do feel that the burden that has been placed on the corporate sector this year largely through withdrawal of concession is fairly high and would,—to an extent,—effect productive activity and growth. But this impact would perhaps be only marginal and not as great as some of the Members of the Opposition benches would like us to believe.

I realise that if this tax burden was not imposed, the growth should have been faster. In any case, the objective factors which exist in the economy are comparatively so good today that notwithstanding this burden, I have no doubt that other things remaining the same, there will be the growth of industries.

In this connection I have only one very specific suggestion to make and that concerns the proposal for withdrawal of the development rebate. I suggest that the Finance Minister should consider extending the period of notice from May, 1974 to May, 1976 so that the schemes that are now conceived can get through and obtain the advantage of development rebate. To my mind, this will go to push the corporate activity and whatever loss is suffered by way of revenue would be more than made up by the increase in corporate earnings and consequently a larger accrual to the Exchequer by way of corporate taxes. This will also help the new entrepreneurs and would be of benefit equally to large and small-scale industries.

I now turn to some of the indirect tax proposals. Everybody in the House seems agreed that the tax on maida was ill-conceived. I would also like to add my voice and plead for its total withdrawal. Maida is mostly used for bread which is the poor man's food. Taxing a poor man's essential food cannot be correct.

Although I would hesitate to suggest specific items, I do feel that the Finance Minister should have thought of increasing excise duties on items which are in tremendous short supply and where the consumer is even otherwise not able to get them at reasonable prices.

This suggestion brings me to what I consider to be an important point. In our country, in some of the industrial products, we have already a tremendous shortage and the consequent ills that flow from it. At the same time there is the danger that shortages may develop in a few other items. The policy being followed by the Government to tackle the shortages through formal or informal price controls is, to my mind, not a right one. By doing so, we unwittingly affect the moral fabric of the society and do not really serve the interests of the consumers at large Malpractices occur. I therefore, earnestly suggest that a fresh high-level review of the pricing of the Government must be initiated. The conclusion, to my mind, is that it is not incompatible to release the productive forces by allowing due increase and thereby promote production of such items. The commodities which I have in view are aluminium, paper, chemicals and dyestuffs including soda ash, caustic soda, cement and the like. If Government follows a liberal policy, there may be a temporary rise, but this will help improve the balance-sheets and curb malpractices under which the increases, in any case, go to somebody's pocket. At the same time, this constitute a powerful initiative for expansion in growth of these items.

The bulk of our population comes from the villages. But, unfortunately, the villages have not even got drinking water facilities. In my own constituency I can tell you that many villages have not got drinking water facilities. I am sure when the Finance Minister discusses matters relating to development of villages with the various State Finance Ministers, he will stress upon them the need to provide drinking water facilities in the villages.

Laying roads in the villages is most important and urgent. Many villages have no roads. The produce is actually being carried in the villages by the villagers over their heads, in the absence of proper roads. So, road construction is very essential and priority must be given to lay roads, especially among villages in the backward districts. That is most important.

Mining project at Agnigundala, near Vinukonda needs very speedy work. The progress is very slow. This is a first-class copper zinc mine and can fetch decent foreign exchange and so, I request that top priority must be given to up a melting furnace there, to see that foreign exchange is earned, without further loss of time.

The coastal districts of Andhra Pradesh require one more refinery. At present we cannot develop and we cannot attract petro-chemical industries in the area. I would therefore request the Government to do something about it.

The conversion of Guntur-Macherla metre gauge line into broad gauge is urgent. Because of the Nagarjunasagar project there, agricultural produce has to come to the market, and unless this broad gauge line is put up, it is impossible for them to carry the products to the various destinations. New Railway connection linking up Nadikudi with Babynagar is very important. This survey has already been completed. The work on construction of this line should be earnestly taken in hand so that the problem of long distance can be overcome.

With these words, I once again give my general support to the tax proposals of the hon. Finance Minister and I am sure the House will approve them.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : Mr. Chairman, Sir, for the past three days, discussions are going on with regard to the Budget proposals introduced by the hon. Finance Minister. This Budget has generally evoked great attention and also strong criticisms from various political parties in the country. Not only that. The entire budget proposals have been evaluated and critically analysed in the context of the Congress party having got a massive majority in the recent mid-term elections.

[Shri P. Venkatasubbaiah]

Though a budget as envisaged in the economic parlance is an annual feature for any Finance Minister, yet, this precent budget is significant in the impact that it can create among the masses of our country.

One fact has clearly emerged after the recent elections. The electorate has chosen and has given its verdict in the clearest terms possible in favour of the left-of-the-centrist policies that have been enunciated by the ruling party in its election manifesto. Another factor that has emerged from these elections is that the main Opposition group in the Lok Sabha is the Communist Marxist group. So, it is clearly evident that the people who have chosen this party to come into power have also shown the direction that we should take, namely that as an alternative, the pendulum cannot be swung back but it has to go more radicalist. This is a clear evidence of the fact that whatever impact the budget can make can be viewed from the context of the alleviation of the sufferings of the general masses.

While introducing the budget, the Finance Minister has set out certain criteria and framed certain guidelines. We have, therefore, to see whether he has followed those criteria and kept up to the norms which he has himself enunciated.

One thing is very clear, namely that the Finance Minister has to do some right-rope walking. He has to augment the resources of the country as a first step towards ushering in social justice and economic equality in this country. Our main concern is to see whether this honest attempt on the part of the Finance Minister is going to be accepted and is going to be appreciated and implemented by the people of the country.

Our country is today facing not only internal pressures but also the threat from our neighbour Pakistan. The unprecedented influx of refugees numbering about 5.5 million in our country has posed a very serious problem not only to our economic stability but also to our political integrity and national security. This has to be borne in mind when the critics begin to criticise the budge.

Secondly, a plea has been made for giving more autonomy to the States and to give them more financial allocations from the Central Government. The recent DMK proposal in this connection through the Rajmannar committee's report should not be viewed lightly. It has got its repercussions on the Centre-State relationship, not only in the political aspect but also in its financial and economic aspects. Time and again it has been the slogan of some of the State Governments who do not have any other slogan, to say that the Centre is appropriating all powers and, therefore, the Centre should part with some of its powers to the States especially in the matter of financial allocations. The other day, through a non-official resolution, they demanded the setting up of a Federal Debt Commission to look into the financial aspects of the States Governments and also to make the Central Government part with more and more of their financial functions to the States.

The third major problem that we are facing in our country is the problem of massive unemployment. The Finance Minister has suggested some crash programmes for solving this problem. But the problem is so great and massive that by merely allotting a few crores of rupees, we shall not be able to solve this problem completely. The problem of unemployment of the educated youth is a big one. I would only suggest to the Finance Minister that to solve this enormous problem of unemployed educated youth, he should constitute a sort of revolving fund to which he could ask the educated youth after they have been employed to contribute something.

So far as the crash programmes are concerned, rural development works are being undertaken. I would like to bring to the notice of the Finance Minister that the production of khadi also should be included in these rural development works. I do not know about other States, but in my State, thousands of families, especially from the Harijans and other backward communites, supplement their income by mass spinning and weaving. So, khadi production should also be an item included in these rural development works.

Some time back, our Irrigation and Power Minister had said that the work of

linking up the Ganga with the Cauvery should be taken up. This is a grand programme which was envisaged a long time back by Mr. Cotton. I would re-emphasise this, and urge Government to take up this work. It may be a stupendous work involving crores of rupess, but ultimalely it will prove to be a great boon for the whole country. It would provide employment not only to technical people but also to non-technical people. Besides, it will also promote national integration. So, the linking up of the Ganga with the Cauvery is a project which has to be looked into.

Another suggestion which I would like to make is a crash programme for providing houses to the unfortunate and weaker sections of t e community. I do not find much provision having been made for providing houses or house-sites for these people; there is not even provision made for drinking water supply. The hon. Member who preceded me had also emphasised this fact.

The next thing that I would like to emphasise is in regard to agricultural production. We should not be complacent. When we look into the economic growth rate of 5.5 per cent, we find that the major portion of the growth is attributed to agricultural production. Industrial production is as low as it was before. Our country has been fortunate to have successively favourable monsoons, and, therefore, increased agricultural production. But we should not be carried away by the impression that agricultural production is going to be on the same level as it was before.

Every effort has to be made to see that industrial production comes up to our expectations. With huge public sector undertakings in our country, it should also be our endeavour to see that industriai growth comes up to the level of agricultural growth.

On the agricultural sector, I would also like to caution the Government that though the acreage under irrigation has increased year by year, the per-acre production has not proportionately increased.

This has to be borne in mind.

Then there is the question of dry farming for which provision has be made.

Then I would request the Finance Minister and the Prime Minister to go into the entire gamut of centre-state relationship in a very thorough manner and evolve a workable relationship. I placed the other day for a permanent Finance Commission to go into this matter to see that centre-state relationship is put on a firm footing so that the present bickerings may not be allowed to go on any further.

As my time is up, I conclude by saying that the duty on maida and other things should be dropped.

श्री दुर्गादास भाटिया (अमृतसर) जो बजट हमारे सामने पेश हैं मैं उसका स्वागत करने के लिए खडा हुआ हूं। इस बजट में हमें समाजवाद की झलक मिलती है। इसमें कोई शक नही कि जो जनता के मन में था या उसका खयाल था कि बहुत कुछ उसके लिए इस बार बजट में होगा, वह नहीं है लेकिन हालात के मुताबिक जो कुछ इसमें रखा गया है, वह अपनी जगह पर सही है। बंगला देश की वजह से हमारे सिर पर बहुत ज्यादा खर्चा पड़ गया है। फिर भी मैं समझता हूं कि इसके अन्दर हमें एक डायरेकशन मिलती है सोशलिज्म की तरफ जाने की और आगे बढ़ने की। समाजवाद एक या दो साल में नही आ सकता है। आपको याद होगा कि जब हमने पांच साला योजनायें बनानी शुरू की थीं तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इन योजनाओं के प्रति हम सब की जिम्मेदारी होगी फिर चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। अपनी शक्ति के मुताबिक सबको बोझा बरदाश्त करना होगा। हमने देखा कि योजनाओं में हमने किस कद्र तरक्की की। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में किस कद्र तरक्की हुई। हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारा रास्ता लम्बा हैं। इसलिए एक या दो

[श्री दुर्गादास भाटिया]

बजटों में यह चीज तय नहीं हो सकेगी। हमें एक लम्बे रास्ते के लिए तैयार रहना होगा। हमें देखना होगा कि जिस कद्र हम खर्च कर चुके हैं, क्या प्रोडक्शन उसके मुताबिक हुआ है? मुझे यह कहते हुए दुख जरूर होता है कि जिस कद्र हम खर्च कर चुके हैं उसको देखते हुए प्रोडकशन का लैवेल उस कद्र नहीं बढ़ सका है जिस कद्र बढ़ना चाहिये था। पब्लिक सैक्टर में हमारा जो काम हो रहा है वह स्वास्थ्यमय नहीं है। प्राइवेट सैक्टर के अन्दर इस बात की चर्चा है कि पब्लिक सैक्टर कामयाब नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि यह एक चैलेंज है जिसको हमें स्वीकार करना होगा और जहां जहां कमियां हैं, उनको दूर करना होगा। अगर ढांचा उसका खराब है तो उसको बदलना होगा, इंतजाम को बदलना होगा और साथ ही साथ पब्लिक सैक्टर का जो दायरा है उसको बढ़ाना होगा। लेकिन यह तभी हो सकता है जब ढांचे में जो कमियां आ चुकी हैं और उनकी वजह से प्रोडकशन उस कद्र नहीं बढ़ रहा है जिस कद्र बढ़ना चाहिये, उनको दूर करें और ढांचे को ठीक करें। ज्यादातर पब्लिक सैक्टर में काम इसलिए कम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैवेल पर मंजूरियां मिलने में सालों लग जाते हैं। उस बीच पब्लिक सैक्टर की जितनी मशीनरी है उसमें से पचास परसेंट बेकार पड़ी रहती है। यह केवल इसलिए होता है कि फैसले देर से होते हैं।

हमें इस बारे में कोई कमीशन बिठा कर यह देखना होगा कि जब प्राईवेट सैक्टर इतनी कामयाबी के साथ चल रहा है, तो फिर क्या वजह है कि पब्लिक सैक्टर ठीक तरह से नहीं चल रहा है। जब तक पब्लिक सैक्टर अच्छे तरीके से नहीं चलेगा तब तक आमदनी नहीं बढ़ सकती है और जब तक आमदनी नहीं बढ़ती है तब तक टैक्सों का बोझ और भी बढ़ाना पड़ेगा।

जहां तक डायरेक्ट टैक्सेशन का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूंगा कि 1939 में एग्जेम्पशन लिमिट 2000 रुपये थी। आज 1971 में, जब कि करेन्सी का फैलाव बीस गुना बढ़ चुका है और कीमतें पंद्रह गुना बढ़ चुकी है, 6000 रुपये की एग्जेम्पशन लिमिट मौजूदा हालात से मेल नहीं खाती है। हम कहते हैं कि हम निचले दर्जे के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इस लिए यह जरूरी है कि मौजूदा मंहगाई और करेन्सी के फैलाव को देखते हुए एग्जेम्पशन लिमिट को 6000 रुपये से बढाकर कम से कम 10,000 रुपये कर दिया जाये।

मंत्री महोदय ने यह यकीन दिलाया है कि नीचे के लोगों की सुविधा के लिए इनकम टैक्स के सिस्टम को सिम्पलीफ़ाई कर दिया जायेगा। इसके लिए एक तो एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया जाये और दूसरे, वैल्थ टैक्स इनकम टैक्स और एसेसमेंट के लिए पहली रिटर्न वगैरह चार चार रिटर्न्ज भरने के बजाये सिर्फ एक ही रिटर्न भरी जाये। चूंकि एक ही अफ़सर फैसला करने वाला होता है, इसलिए उसका टाइम भी बच जाएगा। वह बड़े टैक्स-गुज़ारों के लिए ज्यादा टाइम निकाल सकेगा और ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल हो सकेगा। आज हालत यह है कि पचास साठ हजार कमाने वाले स्माल-स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट्स और इदारों को चार चार रिटर्न भरनी पड़ती है और उन्हें परेशान कर दिया जाया है।

जो सबसे पहले इनकम का अन्दाजा लगाने की रिटर्न दी जाती है, उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि इससे ब्लैक बढ़ी है। अगर इस सिलसिले को बन्द करके एक ही जगह पर सारा इन्तजाम किया जाये तो यकीनन इनकम टैक्स अफ़सर के पास

ज्यादा टाइम होगा कि वह केसिज को अच्छी तरह से देख सके।

जहां तक इनडायरेक्ट टैक्सिज का सम्बन्ध है, मैदा और कोर्स क्लाथ पर जो लेवी है, सब तरफ से उसकी चर्चा हो चुकी है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को यह गलतफहमी हुई है कि मैदा अमीर आदमियों की खुराक है। पंजाब, काश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में मैदा आम तौर पर इस्तेमाल होता है। इसलिए इस पर लेवी लगाना दुरुस्त मालूम नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय मैदा और कोर्स क्लाथ के बारे में जरूर ख्याल करेंगे।

मै मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि एयर इंडिया पर जो बीस परसेंट लेवी लगी है वह भी किसी हद तक जायज नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया एक ऐसी पब्लिक अंडरटेकिंग है, जिसने काम्पीटिशन के बावजूद दूसरे देशों में नाम पैदा किया है और कामयाब हुई है। अगर आज उस पर...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री दुर्गादास भाटिया : मैं दो मिनट में पंजाब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना टाइम ले चुके हैं। मेरी मजबूरी है। आपको अब और टाइम नहीं मिल सकता है। श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य।

•

SHRI CHAPAL BHATTACHARYYIA (Giridih) : At the outset I would call on the hon. Members to move away from the rather theoretical discussion, whether this budget is socialist one or capitalist one or really reflects welfare. It was forty years ago that a noted economist said that the battle of socialism was being won hour by hour. How prophetic that statement was we at this stage can realise. So, whatever may be the nature of this budget that statement holds ground with added force. The battle of socialism is practically half won. This may be a transitional budget, second in a row with a substantial deficit financing and increase in the tax burden as also in the tax effort. But then that is a burden which we have to shoulder for effecting social change. The increase in excise duties, in their rates and coverage, does not necessarily make the tax system regressive. It really depends who has to foot the bill. Except maida, and probably coarse cloth and some varieties of soap, by and large the upper middle-class and the upper classes will have to participate in the payment of excise duties. The question is not whether at one sweep the traditional regressive fiscal system and tax structure could be changed, overnight. But a very bold effort has been made ; there can be no doubt about it. The Kaldorian formula enunciated during the mid-fifties, that wealth tax, capital gains tax, expenditure tax, income-tax and estate duty and gift tax have to be given effect to on the basis of a single return. If there is any lacuna it is with regard to expenditure tax. For, lately there has been a great deal of increase in what veblen called conspicuous consumption. Our friends on the opposite would remember that a socialist by conviction, Dr. Dalton when he took charge of the British finances had to move away from the theretical formulations of progressive taxation and had to reduce direct taxation and go over to excise duties. The main point which Kaldor had emphasised and which holds good today is that the expenditure and wealth tax would have been the main instruments for cornering resources and the disincentive effects which a high rate of taxation on income and the surcharges produce would thereby the done away with. Now we have not implemented the tax on expenditure. There is the other suggestion which Kaldor had made that every account over Rs. 50,000 should be compulsorily audited. That has not been given effect to. There have been loopholes. Estimates of evading taxes vary from a thousand crores to several thousand crores. It has an iceberg quality ; what is visible is probably a fraction of what is invisible. But there has been a chorus of objections against any increase in governmental expenditure what-

[Shri C.E. Bhattacharyya]

soever. I do not fully agree with this view. There is at least one sector where increase in government expenditure may increase Government revenue. We are now spending Rs. 48-50 crores for collection of taxes and duties. The officials of the Finance Ministry can proudly say that we are not spending more than 1 to 1¼ per cent on tax collection which is well in tune with the British budgetary system. But I must point out that at one time the British Finance Ministry officials had to raise this 1 5 per cent to nearly ten per cent. Take the smuggling that is going on. I come from an area in Bihar which exports mica. It has been traditionally exporting Rs. 15 to Rs. 18 crores ; it is now down to Rs 10 crores. Forty per cent customs duty did all the trick. This duty has broken a hole in customs barrier and Rs. 6 to 7 crores worth mica is going to Nepal to be re-exported. If forty per cent export duty can do that trick, we can imagine what probably is happening as we increase the customs duty from 25 to 100 per cent. There has been a substantial increase in excise duties. Honesty has become a scarce commodity and honest implementation has become the need of the hour. We are standing on the great divide for hence forward the evolution which is ahead of us will be materially different from the years which have preceded us.

MR. CHAIRMAN : You have taken nine minutes ; please conclude in one minute's time.

SHRI CHAPAL BHATTACHARYYIA: If you cannot give me even fifteen minutes, how can I make my points ?

MR. CHAIRMAN : I am utterly helpless ; kindly conclude in one minute's time.

SHRI CHAPAL BHATTACHARYYIA: The increase in expenditure on tax collection will substantially increase tax receipts Also the performance of the public sector undertakings have not come up to our expectations. There are more than a hundred incentives which are in use in economically developed countries and we can adopt one of them to increase productivity and production.

We can harness the good will of the labour movement so that all the 79 public sector undertakings or thereabouts, the majority of them are not making profit could make profits, and the position could be very effectively reversed, if we set about doing the thing in the correct way.

17 hrs.

Sir, I come from Chhotanagpur. In the fifties, Mr. Kaldor made a prophetic statement that for 10 million jobs you have to produce 10 million tonnes of extra food. Now, we are faced with the perspective of 30 million jobs to be given, and so 30 million tonnes increase in food stuffs are the need of the hour. Therefore, a much greater drive and a wider coverage has to be given to the crash programmes and all other associated programmes for increasing the production of food (*Interruption*).

I come from a very backward region, ore-crop area, the Chhotanagpur plateau, with only a few industries. But we are importing Rs. 100 crores worth of cotton. Our soil is the best-suited for cotton. So, if we spend Rs. 1 crore a year, this cotton could materially alter the situation.

MR. CHAIRMAN : Now, may I request hon. Members to co-operate with me ? Quite a few more Members are anxious to speak, and the time is extremely limited, Kindly be co-operative and be considerate to the other Members who want to participate in the debate. (*Interruption*) I am helpless in the matter.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : Please allow a Member to participate either in the debate on President's Address or on the budget or on the Finance Bill. Otherwise, many hon. Members would always be left. Earlier, there was a rule that a Member would be allowed to speak once either in the debate on the President's Address, or the budget or the Finance Bill.

MR. CHAIRMAN : I am afraid I cannot plead guilty on that score. It should

be taken up with the Minister of Parliamentary Affairs, All that I can say is, the time is limited and quite a few more Members are anxious to participate and make their contribution. Yes, Mr. Shiv Nath Singh. Please conclude within eight minutes.

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : माननीय सभापति जी, इस बजट के संबंध में सदन में और सदन के बाहर विभिन्न प्रतिक्रियायें हुई हैं। कई साथियों ने इस बजट को अपने हिसाब से बहुत प्रोडक्टिव बताया है और कई साथियों ने रिएक्शनरी बताया है, अनप्रोडक्टिव बताया है। मै निवेदन करना चाहूंगा कि आज की वर्तमान हालत में जोकि इस समय देश में है, उसमें इससे कम कुछ भी नहीं किया जा सकता था। जो बजट पेश किया गया है वह आज के वातावरण में, आजके हालत में बिल्कुल फिट न हो लेकिन इससे कम नही किया जा सकया था। आज इस बजट में कोशिश की गई है कि कहीं पर वेल्थ एक्युमुलेट न हो। इसको चेक करने के लिये, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कारखानों में काम करने वालों की तनखाह पाँच हजार से अधिक नहीं रहेगी और एक हजार से ज्यादा एलाउन्स नही रहेगा। इसी तरह से कुछ दूसरे प्राविधान भी रखे गए हैं और यह कोशिश की गई है कि चन्द हाथों में वैल्थ एक्युमुलेट न हो। हम इस बात का स्वागत करते हैं लेकिन जहां वेल्थ एक्युमुलेट होने का सवाल है उसको उसी समय साथ में देखना पड़ेगा जब आप टैक्स लगाते हैं कि उससे रिलीफ किसको मिलनी है। देश में लोगों ने यह कभी नहीं कहा था कि टैक्स न लगाये जायें। आज लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि टैक्स लगाये जायें लेकिन साथ में उनकी हालत भी सुधरे। चुनाव के समय में हमने बहुत सी बातें कही थीं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को जगाया था। जब बजट सामने आता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं कि क्या इसीलिए हमने इतना बहुमत दिया था कांग्रेस को और इन्दिरा जी कि इतना ही बजट आयेगा और इस बजट से गरीब लोगों को कोई संतोष नहीं है। उन्होंने सोचा था कि उनके लिए मकान बनेंगे। पढे लिखे लोगों ने सोचा था कि उनको नौकरी मिलेगी। काश्तकार ने सोचा था कि उनको पंपिंग सेट्स के लिए लोन मिलेगा। हर आदमी समझता था कि गरीबी दूर होगी। सड़क पर सोने वाला यह सोचता था कि उसको किराये पर घर मिलेगा। लेकिन आज हम इस बजट में इस बात के लिए प्रविधान नहीं कर सके हैं। मैं यह मानता हूं कि कुछ प्राविधान करने की कोशिश की गई है लेकिन वह बहुत नाकाफी हैं। जैसा हमने वायदा किया था उसके अनुसार हस बजट में बहुत कम रख रहे है। मै यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज के बदले हुए वातावरण में जैसा जनता ने हमारा साथ दिया था' इस देश के पूंजीपति इस बात से डर गए थे कि इस चुनाव के बाद पता नहीं हमारी क्या गति होने वाली है। सन् 1947 में राजा-महाराजाओं और बड़े बडे जागीरदारों को डर लगा था कि आजादी के बाद में अब हमारी क्या गति होगी। हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने उनको अभयदान दिया। आज हम महाराजाओं की प्रीवी पर्स और विशेष अधिकार बन्द करने की बात सोच रहे हैं। हमारे देश का एक हिस्सा कश्मीर भी है जहां बिना मुआविजा दिए जागीरदारों की जागीर ले ली लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हम भी उस वक्त राजा, महाराजाओं के विशेषाधिकार समाप्त कर सकते थे। लेकिन उस समय हम ने उन को प्रोत्साहन दिया, उन के साथ में सहयोग किया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ सहयोग नही किया। यही हालत आज के उद्योगपतियों की भी है वे किसी प्रकार का कोई भी सहयोग हमारे साथ करने को

[श्री शिवनाथ सिंह]

तैयार नही है। इस चुनाव में कांग्रेस को जो बहुमत मिला है उस ने देश को एक नया संदेश दिया, अगर हम ने उस का आभास नही किया तो हमारी क्या हालत होगी ? आज भी कौरपोरेट सैक्टर को छोड़ दिया गया है। आज देश आर्थिक क्रान्ति चाहता है, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन चाहता है। देश में बहुत गरीब आदमी हैं, वे चाहते हैं कि उन पर टैक्स लगे और उस को देने के लिये तैयार भी हैं लेकिन वह साथ ही यह अपेक्षा भी करते हैं कि उस पैसे से उन का कुछ भला हो।

177 करोड़ रुपये के टैक्सेज का प्रस्ताव इस बजट से किया गया है। देश की आबादी 55 करोड़ है जिस का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति पर साढ़े तीन रु० का टैक्स पड़ता है। कोई भी परिवार इस को देने से इन्कार नहीं करेगा। लेकिन वह चाहता है कि इस से ऐसा काम हो जिस से हमारी आमदनी बढ़ सके। लेकिन इस ओर हमारा बजट कहीं भी दिग्दर्शन नहीं करता है। इसलिये हमारा बजट इस प्रकार का होना चाहिये जिस से वैल्थ का ऐक्युमुलेशन बन्द हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो मोनौपली होती जा रही है उद्योगों के मामले में उस पर चैक लगना चाहिये।

हमारे देश में धन की कमी नहीं है। एल. आई. सी. और बैंकों के पास काफी धन है। उस धन को पब्लिक सैक्टर में लगायें तो आम आदमी की भलाई के काम हो सकते हैं। लेकिन देखने में यही आया कि एल. आई. सी. और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी बहुत सा पैसा इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही मिलता है जिस से वह अपने साधन बढ़ाते हैं और आम आदमी की आय में कोई विशेष इजाफा नहीं हुआ है। 23 साल में उद्योगपतियों के पास काफी उद्योग बढ़ते चले जा रहे हैं। इस को रोकने का एक ही रास्ता है और वह यह है कि पब्लिक सैक्टर को बढ़ाया जाये और प्राइवेट सैक्टर पर चैक लगना चाहिये। अगर ऐसा नही किया गया तो हमारी इन्कम का कोई लाभ गरीब आदमी को नही मिलेगा।

इस सदन में ऐग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिये बहुत कुछ कहा गया है। माननीय इन्द्रजीत गुप्ता इस बात को कह सकते है कि ऐग्रीकल्चर पर टैक्स लगना चाहिये। मैं उनकी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जानकारी के लिये कहना चाहता हू कि उन का कहना सही हो सकता है क्योंकि यह ठीक है कि ऐग्रीकल्चर क्लास ने जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी का साथ नही दिया, बल्कि कांग्रेस का साथ दिया है और सम्भवत: यही बात उनको खल रही है। यद्यपि उन्होंने लैंड ग्रेव मूवमेंट चलाया लेकिन उन के शिकंजे में काश्तकार नही आये इसीलिये उन को टीस है। वित्त मन्त्री ने कहा है कि ऐग्रीकल्चर क्लास में बड़े बड़े काश्तकारों पर टैक्स लगना चाहिये। आज देश की जो स्थिति है, अलग अलग प्रान्तों में सीलिंग हो चुकी है उस के बाद मेरी समझ में नही आता है कि अब कौन बड़ा काश्तकार है। कोई भी तो अब बड़ा काश्तकार नही हो सकता जब से सीलिंग लग चुकी है। काश्तकार की तीन, चार हजार रु० सालाना आमदनी मान कर के सीलिंग कायम की है। इसलिये जो गलतफहमी फैलायी जा रही है कि बड़े बड़े काश्तकार हैं इस को मैं दूर करना चाहता हूं।

मैं राजस्थान से आता हूं वह पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां आये दिन अकाल पड़ता है। पिछले दो साल में लोगों का पेट भरने के लिये

हम ने 150 करोड़ रु. खर्च किये। ऐसे प्रान्तों को, जो अधिक पिछड़े हुए हैं, जहां कि 30, 40 मील की दूरी से पीने का पानी हम को लाना पड़ता है, केन्द्र को अधिक सहयोग देना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि जो अंडर डेवलप्ड प्रान्त हैं उन के विकास के लिये वित्त मंत्री जी अधिक साधन मुहैया करें।

आखीर में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां तम्बाकू पर टैक्स लगाया गया है, लेकिन उसकी वास्तविकता को कोई जानता नहीं है। हमारे यहां ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी तम्बाकू होती है कि जो टैक्स लगाया जाता है उसकी चौथाई कीमत में भी उसको कोई लेने के लिये तैयार नहीं हैं। राजस्थान जैसे इलाके में, जहां पर बहुत खराब किस्म की तम्बाकू होती है, कोर्स वेराइटी की तम्बाकू होती है, वहां पर अगर आपको टैक्स लगाना ही है तो पर एकड़ टैक्स लगाइये, और उसकी दर कम के लगाइये, भले ही आप अच्छी वेराइटी की तम्बाकू पर प्रति पाउंड के हिसाब से टैक्स लगायें। इसी तरह से राजस्थान के लोगों को रिलीफ मिल सकता है, वर्ना एक तरह से सबको हांकना उचित नहीं है।

यहां मैदे की बात कही गई। मैदे का टैक्स ऐसा है जिस को अगर आप हटा भी दें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे ही आप ने मैदे पर टैक्स लगाया उस के साथ ही मैदे की कीमत बढ़ गई। अगर अब आप उस को हटा भी दें तो उस से कोई रिलीफ जनता को मिलने वाला नहीं है। जो डबल रोटी पहले 75 पैसे की आती थी आज वह 80 पैसे की आ रही है। उस के दाम भी कम होने वाले नहीं हैं।

हां पेट्रोल पर जो टैक्स लगाया गया है उस को जरूर हटाना चाहिये। पेट्रोल पर आप ने 20 पैसे टैक्स लगाया है। इतना बड़ा टैक्स कभी नहीं लगाया गया। इस लिये आप पेट्रोल पर टैक्स जरूर हटा दें ताकि आम आदमी भी उस को खरीद सके। अगर आप टैक्स लगाना ही चाहते हैं तो वेल्दी क्लास पर लगायें। आप कार-परचेजिंग पर टैक्स लगायें। अगर आप पेट्रोल पर टैक्स लगाते हैं तो उस से कामन मैन सफर करेगा। इस लिये आप को पेट्रोल पर से तो टैक्स हटा ही देना चाहिये।

SHRI S. N. MISRA (Kannauj): Sir, I must congartulate the hon. Finance Miaister for having given an impression that a new trend in the budget has been created and the trend that has been created is creating an impression that there will be a ceiling on income and holdings. I am not sure whether we shall succeed or not, but that is an impression that has been created and that is likely to advance our interests and the interests of the States because people would think that their accumulation would not be useful to them. Whether we succeed or not, we will at least succeed in creating an impression in the future.

We have certainly heard complaints from the poor and middle class people. One evening they presented a couplet before me which I am going to place before the House. What they said was :

दी है राहत के बहाने मुझे ईजा क्या क्या,
चुटकियां सैकड़ों लीं, फांस निकाली न गई।

I know that for a few hundred crores of rupees our hon. Finance Minister has tried to tax X, Y, Z items which may finally result in creating a little discontentment with the poorer sections of the people. I suppose there would be no dispute, it will not be disputable, that money saved is money earned. Unfortunately, our Finance Minister, almost every Minister and every Ministry here, is not guided by their own dictates; they are only guided by the bureaucrats and the clerks of the department. Therefore, I am afraid that all the suggestions that I am making before the

[Shri S. N. Misra]

House will not carry much weight. Yet, duty-bound I consider I must place some suggestions for saving on various items because if we can effect savings we shall have something left and no taxation would be needed.

My first suggestion is about civil expenditure. In 1947 we were expending less than Rs. 50 crores on civil expenditure. In the 1970-71 budget we have spent Rs. 1,500 crores, which is almost 50 times what we spent in 1947. In 1971-72 our budget figure of civil expenditure is Rs. 1,725 crores. If we could make a cut of Rs. 225 crores on this,—I know it is a very little sacrifice for the civil servants, sacrifice in the sence that our poor civil servants will be without air-conditioners, without foreign cars and they will not have some of the amenities which now they are enjoying at the expense of the civil expenditure—if only we could do this, then there will be no necessity for further taxation and this cut in civil expenditure is one which is absolutely indispensable in a socialist country where there should not be any disparities. We should be able to make this cut.

Secondly, we are undar heavy indebtedness. Today we will have to pay Rs. 660 crores as interest. Is this justifiable that we should pay such a huge amount as interest ?

यावत् जीवेत सुखम् जीवेत
ऋण कृत्वा घृतम् पिवेत ।

I do not think it is correct. We should economise and spend first on necessities only, for making the country healthy. To keep on borrowing is not a good policy. Therefore, economy in the civil expenditure of the budget is indispensable.

Then, I have seen in today's papers that the outstanding of income-tax and other dues is about Rs. 800 crores. I know it for a fact that an income-tax officer issues a recovery certificate. It first goes to the tehsildar. Then the tehsildar sends it out to a small man for verification. If you give him a few hundred rupees, he will give a report that he went there, the person is missing, the firm is not existent and the money is not recoverable. So, I would suggest to the Finance Minister that we should follow the tradition which is existing in England of the Citizens' Council or Committee. That Committee assists in the realisation of taxes. If the same principle is adopted then these Rs. 800 crores of outstanding can be realised within a period of one year. I will immediately report that my nextdoor neighbour is a businessman with a good income, he is not dead, his firm is not under liquidation and then recovery would be made. In that case, we shall not need any taxation on any item.

Here I may say that we are going to have a forum for the members of the bar in Parliament. I might assure the Minister of Finance that we, the Members of Parliament and the members of the forum will assist in realisation.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Is it open only to the members of the bar ?

SHRI S. N. MISRA : And also those who have the outlook of the bar. Here may I say for the information of the House that we are having illicit import of gold to the tune of Rs 500 crores and our officials, whether of excise or customs, are aware of this fact ? The smugglers and black-marketeers fill their pockets and import Rs, 5,000 crores worth of gold. The officials will catch a few and show that they are doing very good work. I would request the Finance Minister to scrap the Gold Control Order. Let there be free import of gold into this country and let it be taxed. Do not allow them to make a profit. Now our money is spent, foreign exchange goes out in an oblique manner, which is known only to the officials and we do not get any benefit. So, that order must be scrapped.

Thirdly, we are spending a lot of money on prohibition. I know there are ideologies of Mahatma Gandhi which are being followed more in breach except in the case of prohibition. I am an absolute teetotaller myself. I think that instead of

creating about two lakhs of people who are criminals, instead of causing deaths of hundreds by the illicit liquors that they are producing, prohibition should be completely scrapped. We shall be able to get at least Rs. 300 crores if prohibition is lifted.

We are spending Rs. 30 crores on our foreign offices. And who man them? They are either ICS or IAS officers who never had sympathy with me, with the Government or with the country's aim. Either the rajas or the maharajas have been placed in charge of those offices, with the result that Pakistan had better propaganda than what we have done in respect of the Bangla Desh issue. Therefore we must be able to economise on this head also.

The less said the better about the public undertakings. About taxation also I remember another two lines. They are :—

चले हैं लूटने सैयादो-बाग़वां दोनों
वह चार तिनके जो बाकी हैं
आशियाने के,
मेरे नशेमन के चार तिनके जो मेरी
मेहनत की मिलकियत है,
अगर सलामत नही रहे वह, तो मैं
बहारों को क्या करूंगा।

Therefore do not tax people, economise on these and if you really have to tax, take only one item. The Population Control Act should be there and we should be able to tax people getting more than three children at the rate of one-sixth, if they are more, at one-sixth and if there are still more, at one-fifth.

SHRI P. R. SHENOY (Udipi) : MR. Chairman, the burning problem that our country is facing today is that of vast unemployment and I am glad that the hon. Finance Minister has taken note of this fact while presenting the Budget before this House. The problem can be solved by rapidly increasing the constructive economic activity all round the country on a war footing. As a beginning the Finance Minister has increased the Central Plan outlay for the year 1971-72 by Rs. 155 crores. He has also allotted Rs. 25 crores for creating job opportunities for educated unemployed in addition to Rs. 50 crores allotted for rural employment. He has also indicated that the policy of rapidly increasing the number of branches of nationalised banks will continue.

17.23 hrs.

[SHRI K.N. TIWARY *in the Chair*]

Considering the urgency and the gravity and the massive nature of the problem, I would say that the hon. Finance Minister should have been bolder by allotting larger amounts for the plan outlay and for creating job opportunities. He could have also stated that the policy of rapidly increasing the number of branches of nationalised banks would be pursued more vigorously.

The vast resources of this country can be fully and successfully exploited only in partnership with fellow countrymen. It is said that an idle brain is a devil's workshop but I do not know what an idle brain with idle hands and an idle stomach is like. We are today exporting iron ore and other ores to Japan and other countries because we do not want to make better use of them. Large quantities of iron ore of excellent quality are found in Kudremuk in Mysore State and we are already negotiating with foreign countries to dispose of this ore with least trouble to ourselves. I suggest that the Government should establish a steel plant in coastal Mysore to make the best use of the iron ore that is available in Kudremuk. I also suggest that the Government should go ahead with its plan for establishing new plants and for exploring the possibility of getting more ore and establishing more plants

It is the duty of Government to utilise the full capacity of public sector undertakings. At present the utilisation of capacity in Durgapur steel plant is only 39.6 per cent and in Hindustan Steel as a whole is less than 60 per cent. The utilisation of capacity in Heavy Engineering in the year 1970-71 was less than 25 per cent. The Government must find out the causes for this underutilisation and find out quick remedies so

[Shri P. R. Shenoy]

that all these public undertakings may be utilised to their fullest capacity.

The Finance Minister has made reference to the efforts that are being made in improving agriculture, but the efforts that are made in improving fisheries are far from satisfactory. The Government should give due consideration for deep sea fishing and should build up small fishing harbours along the long seashore that this country possesses. This country must also have more refrigerated vans for transporting fresh fish from one place to another.

The progress of certain projects that are undertaken by the Government is very poor. The Mongalore harbour is an example. The work on Mangalore harbour began in the year 1964 and crores of rupees have already been invested but the most important work of dredging has just begun. With the present dredging pattern I do not know how many years it will take to complete the work. We are told that by the time the work is completed the harbour will become out of date because it will have only a thirty-feet draught and ships weighing more than 25,000 tonnes cannot enter this harbour. I suggest that the Government must increase the depth of the draught to 40 feet and complete this work as early as possible.

Regarding taxes I must say that this country can have no real progress unless there is corresponding sacrifice on the part of the people. This sacrifice is made by way of paying taxes. Any finance minister of a developing country has to impose some taxes, direct or indirect, and directly or indirectly. However, I request the Finance Minister to give due consideration to the criticism made by Members of this House regarding the levy of taxes on items such as maida and coarse cloth.

Great concern is shown by all sections of this House regarding the rise in prices of essential commodities. The only remedy appears to be demonetisation of hundred-rupee and ten-rupee notes with a view to bring out unaccounted money. However, care should be taken to see that innocent persons do not suffer by this measure.

With these observations and with sympathies to millions of refugees from Bangla Desh for whom a sum of Rs. 60 crores has been allotted in the Budget, I support the Budget.

SHRI A. N. VIDYALANKAR (Chandigarh): Mr. Chairman, I think that the general tone of the speech of the Finance Minister was really progressive and the Budget proposals are also progressive. This is unprecedented. Some of the principles which he enunciated in the course of his speech were never properly put in that clear manner. The intentions that he expressed in the Budget were admirable and unexceptionable and I welcome them. I think, even the levies that are criticized here, for instance, the duty on maida, toilet soap, cotton fabrics etc., are also not so excessive. Although I do not support them. If we analyse the whole thing, it increases the family cost by only one rupee per month per kilogram on account of maida. On toilet soap, the increase is only 2 p per cake. In the case of cotton fabrics, it is 1 to 5 p. per metre and in the case of coarse cloth, it is only 0.5 p per metre. As regards lipsticks, shampoos and hair oil also, not more than 8 annas per month will be the increase in the family budget.

Now, Sir, although this increas is not much, why the common people object to this. The common people will not object to paying more. They are prepared for all kind of sacrifices provided they find that the other classes, the upper classes, the richer classes, also made sacrifices. When the common man sees that the big officers, the Ministers and the rich people were going about in luxurious cars, living in luxurious bungalows, just as it was mentioned here, when any ceremony takes places, they use a lot of electricity and all that, then they begin to feel why should their maida only be taxed? They do not object to pay more. But the main thing is the whole trend, the whole purpose and the whole attitude is found to be pro-upper classes. The richer classes, should be taxed more. In this Budget, the Finance Minister has made that attempt, I should say, an admirable attempt

to place the burden on those classes that can pay more. But the feeling is that more burden could be placed on them.

This Budget is a welfare Budget. The welfare Budget is not necessarily a socialstic Budget just as all philanthropy is not scientific socialism. A Budget which claims to be a socialistic Budget should try to control the commanding heights of economy. Whether the Budget tries to control the commanding heights of the economy, whether we acquire that grip, that grasp, over the whole economy and whether we can use the economic institutions as an instrument for the attainment of social justice that is the test. The common man looks from that angle and does not feel much enthusiastic about the Budget.

Why is it so ? The main reason is that the instrument of our attaining socialism is the present bureaucracy and the present bureaucracy has no sense of commitment to our ideals. Unless that instrument is properly sharpened which is absolutely blunt-at present, we cannot succeed. The bureaucracy is not working for the attainment of that objective, it is clear. We should find out methods as to how bureaucracy can be improved.

Mr CHAIRMAN : The hon. Member may try to conclude now.

SHRI A N. VIDYALANKAR : I only want that the Finance Minister should have explored other avenues, say for instance, the expenditure tax, the capital levy and all that. Why should not there be a total ban on the import of luxury goods ? Take, for instance, the rich people who enjoy luxurious living in 5-star hotels. Why should not the expenditure incurred by them in these 5-star hotels be taxed ? Why should not luxurious expenditure be curtailed ? Why should not the Government expenditure be drastically curtailed ? If we examine properly, we will see that the Government expenditure is growing day by day. It would be practically consuming what we try to squeeze from the public. Therefore, these are the things over which we should lay our fingers. The Finance Minister had stated that the taxation should be such that it should control the rise of prices. But, no drastic measures have been taken to control the prices.

My hon. friend, Mr. Vajpayee, in the course of his speech, suggested the auctioning of licences. He has suggested a method by which he is trying to support those classes that try to monopolise everything. He means, if the licences are auctioned, rich class should monopolise everything. We want to remove monopolies in our economy. In Chandigarh, I see, lands are taken from the peasants at a very cheap rate, they are made into plots and auctioned, and the rich people are buying property and they are amassing property. Why should this go on in our present economy which aims at socialism ? Therefore, this method of auctioning of licences that has been suggested by Mr. Vajpayee, the leader of the Jana Sangh party, can never be accepted. Whatever suggestions he has made are all in support of those classes whom we want to dispossess and from whom we want to take away monopolies. So, we should not adopt those methods. This method of auctioning property will create concentration of wealth and that will give wealth to those classes that are already in possesstion of wealth.

श्री हरी किशोर सिंह (पुपरी) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बजट में जो सामान्य कर का प्रस्ताव है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं वित्त मन्त्री जी से सहमत हूं जहां उन्होंने कहा कि सिर्फ बजट और वह भी एक साल के बजट द्वारा यह सम्भव नहीं है कि समाज में बुनियादी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सके। यह ठीक है कि एक साल के बजट के द्वारा ऐसा करना सम्भव नहीं है। लेकिन वित्त मन्त्री जी के उस वक्तव्य की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां उन्होंने कहा है कि तीन महीना पहले सरकार को जनता से जो भारी आदेश मिला था वह समाजवाद के साथ साथ तीव्र आर्थिक विकास के लिये था।

[श्री हरिकिशोर सिंह]

सामान्य स्थिति में वित्त मंत्री का यह बजट बहुत प्रगतिशील कहा जायगा। मैं कह सकता हूं कि अभी तक जितने वित्त मंत्री आये हैं और उन्होंने जो कर प्रस्तावना की थी उस दृष्टि से यह काफी प्रगतिशील है और समाजवादी दिशा में हमारी प्रगति का द्योतक है। लेकिन बुनियादी प्रश्न जो उठता है वह यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ? जिधर हम जा रहे हैं उस दृष्टि से हमें कुछ निराशा हो रही है।

वित्त मंत्री ने कम्पनियों पर कर लगाया है उसकी मैं सराहना करता हूं। उन पर अधिक कर लगना चाहिये था, खासतौर पर कौरपोरेट सेक्टर पर। मैं उन लोगो मे भी नही हूं जो वित्त मन्त्री के कर प्रस्तावों का विरोध 'जनता'' की आड़ में कर रहे है, खास तौर पर मैं उन लोगों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो पैट्रोल पर बढ़े कर का विरोध करते है, या मोटर के पुर्जों पर पर टैक्स लगा है उसका विरोध करते हैं। मै समझता हूं कि देश की साधारण जनता पैट्रोल पर बढ़े हुए कर या मोटर के पुर्जे पर बढ़े हुए कर से प्रभावित नहीं होगी। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हू कि मैदे पर भी टैक्स वाजिब है। यह शहर में रहने वाले थोड़े से लोगों को ही प्रभावित करता है। गांव में कोई भी डबल रोटी, पाव रोटी नहीं खाता। इसलिये मैं इस कर का समर्थन करता हूं क्योंकि मैदे का उपयोग मिठाई के काम में भी आता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के कितने लोग मिठाई खाते है ?

मैं इस बात के लिये भी वित्त मत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने डाइरेक्ट टैक्सेशन के कुछ बहुत अच्छे प्रस्ताव किये हैं। लेकिन जहां उन्होने यह दावा किया है कि यह कर प्रस्ताव जो उच्चतम आय समूह की आमदनी पर लगाये गये हैं या धन कर (wealth tax) की दर में वृद्धि की गयी है वह वह बहुत कठोर हैं और कठिन हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, और न इससे आर्थिक विषमता को कम करने की दिशा में खास प्रगति ही होगी। मंत्री महोदय ने स्वयं कहा हैं कि इससे केवल 14.5 करोड़ रुपये मिलने की सम्भावना है और वह भी अगले साल। इस साल कुछ नहीं मिलेगा। अगर सामाजिक न्याय और आर्थिक विषमता को दूर करने की दिशा में हम कोई कठोर टैक्स लगाते है ओर उससे सिर्फ 14.5 करोड़ रुपये मिलने की सम्भावना हो तो इससे बहुत लाभ होने वाला नहीं है। अगर हमारे वित्त मंत्री जी यह अपेक्षा रखते हैं कि आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये यह आमदनी काफी होगी तो मै समझता हूं कि इस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में वित्त मंत्री जी या तो कोई गहरी गलतफहमी में हैं या फिर यहां कोई आर्थिक विषमता है ही नही जो 14.5 करोड़ रुपया कर के रूप मे लगाकर दूर की जा सके।

अब मैं कृषि के क्षेत्र पर आता हूं। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में काफी असमानता है। मैं स्वयं एक कृषि क्षेत्र से आता हूं और किसान परिवार का हूं। गाँवों में काफी आर्थिक विषमता है। साथ ही वहां पर सामाजिक विषमता भी है, जिसको अभी तक दूर नहीं किया गया है। यह हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है। हमारे यहां बहुत से भूमि सुधार के कानून पास किये गये हैं, लेकिन मै इस बात से सहमत हूं कि देश में और राज्यों में जो भी भूमि सुधार के लिये कदम उठाये गये हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में देश में एक अनिश्चित वातावरण है। बड़ा किसान सोचता है कि पता नहीं कि कब भूमि सुधार कर दिया जाये और उसकी भूमि ले ली जाये और छोटा किसान भी भूमि सुधार की समस्या से त्रस्त है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भारत

सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये जो निश्चित कदम हों और भूमि सुधार के सम्बन्ध में एक फाइनैलिटी हो जाये, क्योंकि इसके न होने से उत्पादन पर बड़ा खराब असर पड़ रहा है। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस दिशा में संकेत किया है लेकिन, अगर केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं है तो उसको संविधान में संशोधन करके भूमि-सुधार के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाना चाहिये।

राज्य सरकारों पर भूमिपतियों का प्रभाव अधिक रहता है और वे भूमि सुधार की प्रगति में बाधक रही हैं। अतः भारत सरकार ही इस सम्बन्ध में ठोस प्रयास कर सकती है। आज कृषि के क्षेत्र में लगान माफी का वातावरण सा बन गया है और हर पार्टी के लोग इसमें शरीक हैं। आज समाजवादी और दूसरे दलों के लोग भी चाहते है कि कृषि के क्षेत्र मे भूमिसुधार कानून बनाया जाये लेकिन साथ साथ वे लगान माफी का भी नारा दे रहे हैं। इसलिये केन्द्रीय सरकार ही अब कोई ठोस कदम उठा सकती है। मगर साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृषि सुधार में केवल भूमिसुधार ही सम्मिलित नहीं है। मैं चाहूंगा कि देहातों में कृषि सुधार के लिये और भी साधन हों तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये और ठोस कदम उठाये जायें। इसके लिये मुझको कुछ सुझाव देने हैं।

देहातों में प्रखण्ड स्तर पर कृषि केन्द्र स्थापित किये जायें और उन कृषि केन्द्रों से किसानों को बीज की सुविधा मिले, उन्हें ऋण की सुविधा मिले तथा अच्छी फसल के लिये खाद की सुविधा भी मिले। हमारे वित्त मंत्री जी ने साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण करके बहुत अच्छा काम किया मैं चाहूंगा कि साधारण बीमे के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका विस्तार कृषि क्षेत्र में भी किया जाये। बहुत दिनों से यह बात सुनने में आ रही है कि फसल बीमे की योजना होगी, इसको कार्यान्वित किया जाना चाहिये। इस साल उत्तर भारत में फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे पता नहीं है कि जिन किसानों ने ऋण लेकर कृषि में लगाया है, उसकी लागत की भी वसूली कैसे होगी और अगले साल खेती कैसे होगी। इसलिये आवश्यक है कि देहात में क्राप इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाये जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिले।

अन्त में मैं उस महत्त्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जिसकी चर्चा वित्त मंत्री जी ने भी की है और जो हम सभी के दिल दिमाग को झकझोर रहा है देश बहुत असमान स्थिति से गुजर रहा है। असमान स्थिति को सुधारने की दिशा में पिछले आम चुनाव में जनता को बहुत आशा बँधी थी, लेकिन वह आशा निराशा में बदलती चली जा रही है। मैं नहीं समझता हूं कि इस बजट के द्वारा हम देश में समाजवाद ला देंगे या गरीबी मिटा देंगे। लेकिन इस दिशा में ठोस कदम अगर हम नहीं उठायेंगे तो राष्ट्र और जनता में जो भावना जागृत हुई है, जनता की आकांक्षा बढ़ी है, अगर उसको हम पूरा नहीं कर पायेंगे तो फिर देश में उसी तरह का निराशा का वातावरण पैदा हो जायेगा, जो आज से छः सात साल पहले था और शायद हमें जनतान्त्रिक तरीके से इस देश की सामाजिक एवं आर्थिक-व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने का अवसर नहीं मिलेगा।

DR. H. P. SHARMA (Alwar): Mr. Chairman, Sir, the present Budget, coming as it does, in the wake of the recent General Elections, assumes far greater importance than a Budget presented in the

[Dr. H. P. Sharma]

regular or normal year. Even in a normal year the Budget gives concerete evidence as to how far the Government is willing to go to implement its progressive aims and policies. But, since our last General Election was fought on specific issues, this House as well as the country, has a right to expect that the Budget would reflect the hopes and aspirarions aroused in the minds of the public.

The commitments and the promises we made to the public in the context of the problems of the country can be broadly summarised under three or four heads.

Our first commitment was that we would accelerate the rate of economic growth. Our second commitment was that we would try to reduce the disparities between the different sections of our population. The third commitment was that we would take some significant steps towards solving the problem of the unemployed. These were the commitments that we made.

Sir, the Budget has been called a retrograde Budget, an anti-people Budget and quite a few other epithets have been used to disapprove of the Budget. I certainly do not belong to that cadre of people who start with a defeatist attitude of mind.

The country has made some significant progress and we have taken some very significant steps in the direction of the country's development and I think, it is in the fitness of things, that we should remember and recall our successes also as our failures.

During the past year and in the first two years of the Fourth Plan, we have succeeded in fulfilling the objectives of this Budget attaining the assigned rate of economic growth. We have been able to fulfil in both the segments, in the agricultural sector as well as in the industrial sector. Apart from that, food production went up to 106 million tonnes though there were some gaps as regards pulses and a shortfall in cash crops. But this does not in any way minimise the success which we have achieved on our agricultural front.

I would like to make one other observation before I proceed further. I would like to sound a note of caution. We must not count our chicken too fast. There is the element of of help from the Gods. For the past 4 years, the monsoons have been pretty regular and the quantam of rain sufficient. Agricultural production depends still to a large extent on the regularity of monsoons. It rests on a very slender and tenuous base. I wish the Government would keep that margin of uncertainty in mind in the rate of progress that we might assign to ourselves.

The rate of economic growth and everything else depends upon the mobilisation of our resources. The finance Minister has taken some very bold steps in this direction.

First there was the nationalisation of Banks and then the nationalisation of General Insurance. That has provided us funds which we can channolise into productive directions which we could not do previously. There are other things which we have been able to do and which I would to like enumerate here. For instance in the taxation items, there have been increase in the personal income-tax, in the rate of corporate taxes, in the rate of wealth tax etc. whereby a virtual ceiling has been imposed, and the Finance Minister deserves to be congratulated squarely on this.

There have been other welcome features of this budget namely that resolute steps are to be taken against benami holdings, undervaluation of property etc., and we find that Government have a strongly mind to share in the long-term capital gains that people make.

There are other sectors to from which Goverement can collect the resources. For instance, there is the agricultural sector. I do wish that Government would make up their mind and see that they tap this big sector which is going almost untaxed at present. I am not saying in any way, nor nor do I want to be misconstrued, that I am advocating that very small farmer should be taxed. But I think that there are people who are making Rs. 50,000, Rs. 1 lakh and Rs. 2 lakhs a year from the farming. I do not know why farm incomes

of that magnitude should be left out from the purview of taxation. I am not saying thereby that the small farmers or the peasants in general should be taxed. We must remember that the biggest part of our developmental expenditure has been spent on the construction of dams from which irrigation facilities have been provided or from which electricity has been generated which again has gone towards rural electrification. So, the biggest gainers of our developmental expenditure have been in the agricultural sector. So, I do think that Government should shed their old inhibition and tax those people who make very handsome income out of their farms, because an income of Rs. 1 lakh in the agricultural sector is not different from a similar income if it were earned by say a shopping business. Of course, there is a small tax on tractors, and it is good as far as it goes.

There are other sectors from which Government can augment their income. For instance, there are the public sector undertakings. I do not know why Government should be so touchy about this question and why they should be so sensitive every time this subject is brought up. I do not know why somehow it is considered as an attack on the Government's basic policies. I feel that Government have taken a very solid, very resolute and very correct step namely that Government should be the owner of the basic industries in this country. But I does not go along with this proposition that they should be run inefficiently. I think that we must take resolute steps to correct the deficit on this side. I do not want to repeat the various figures, but the case of Hindustan Steel is a case in point. In 1968-69 they had a loss of Rs. 40 crores, in 1969-70, the loss was Rs. 11/- crores; and in 1970-71 it is expected to be of the order of Rs. 12 crores. It may be that Government may have some very valid reasons due to which these losses were inevitable, such as political disturbances etc. But even then, I wish that Government are not touchy about this problem every time the issue of public undertakings is brought up here in this House. Government should serve as a model employer and they should display a model technique of runnning the undertakings, and especially when we have invested such huge amounts in these undertakings, the country has a right to expect that we get proper return from them.

There are other avenues which are open to Government and which Government should tackle resolutely. So far as the recovery of the tax arrears is concerned, I think the entire House, that is the Opposition as well as the Treasury Benches all wish that everything should be done to recover these tax arrears which are of the order of about 900 crores or so. When some of the names of the assessees are publised and we read them, they read like a 'Who is Who' of the biggest capitalists of industry. I think that no leniency should be shown. Here, I would like to make one small suggestion. It is possible that somotimes there may be differences on the assessment, and that is why it is said that the income-tax cannot be recovered. But I think that there should be some time-limit for this purpose, and if the recoveries are not made within that time-limit, then the assessees should at least pay interest on that amount. If Rs. 10 or 20 lakhs is kept pending and the assessees go on doing this business of discussion and disputing, then it is but natural that the assessees should be asked at least to pay interest on these amounts. Why should we be lenient in that regard ?

MR. CHAIRMAN : The hon. Member should try to conclude now.

DR H. P. SHARMA : Please give me two or three more minutes.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member has already taken about 15 minutes. After he concludes, I would like to call another Member also.

DR. H. P. SHARMA : I shall try to finish in two minutes. I shall skip over the other points and come to the question of price rise or price instability. Unless the Finance Minister can solve it, nothing can be done. About Rs. 400 crores were paid as dearness allowance during the last year alone. There is a pay commission which is sitting and which is going to revise the salaries once again. Every time there is a pay commission we know that it revises the salaries upward. So, we can expect that this time also, there would be further pay increases.

Since the time at my disposal is so short, I would in conclusion like to draw

[Dr. H. P. Sharma]

the attention of the Finance Minister to the problem which concerns my State, namely the State of Rajasthan. There has been a notice from the Reserve Bank of India to the Rajasthan Government that by 30th June, they should pay back the overdraft of about Rs. 85 crores. This is good and sound as far as it sounds, but the hon. Minister must see how this money was spent. This was not spent for augmenting the Rajasthan Government's income or anything of that sort. It was spent for humanitarian purposes, for saving the lives of hundreds of thousands of people. The Finance Minister will but be doing justice if he waives this. In cases of national calamity where money is spent, the Finance Minister should not go by the usual alphabetical list of recovery starting from Assam and so on. Then, there is the problem of security also. If you uproot the people living on the border, and they are the first to be attacked by famine. This also must be borne in mind. After all, we have a seven hundred mile-border, and we are doing the function of security on behalf of the nation, and when we are faced with the security problem, the Finance Minister should be considerate to our State.

SHRI SATISH CHANDRA (Bareilly) : I am grateful to you for having called me....

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may please continue his speech tomorrow.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SECOND REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : I beg to present the Second Report of the Business Advisory Committee.

17.59 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 10, 1971/Jyaistha 20, 1893 (Saka).

Printed at The Bengal Press, Delhi-6